fo"k; lwph

संसद में बहस

राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस

लालकृष्ण आडवाणी............ 5
थावरचन्द गहलोत............. 6
जसवंत सिंह...................... 7
अरुण जेटली...................... 8
प्रभात झा........................... 10

आम बजट २००९-१०

प्रतिक्रिया............................. 12
आंकड़ों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं
–यशवंत सिन्हा........... 13
सरकार की अक्षमता का प्रतीक
–अरुण जेटली............ 14

रेल बजट २००९-१०

ढोल के भीतर पोल
–राम नाइक................ 17

विजय संकल्प रैली

हरियाणा(22),गोरखपुर(23),रामपुर (24)

लेख

बांग्लादेशी घुसपैठ
– किरण माहेश्वरी...... 25

राष्ट्रीय परिषद बैठक

7 ,oa 8 Qjojh ukxiqj
कृषि प्रस्ताव........................... 28

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kek
latho dqekj flUgk
jkeu;u flag
पृष्ठ संयोजन
/keZUæ dkS'ky

सम्पर्क
Mk- eqd th Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887

सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

lEikndh;

मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ– इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किये कार्यसिद्धि कैसे हो सकती है।

-श्रीमद्‌भागवत

यूपीए सरकार हटाएं अपना कर्तव्य निभाएं

गत पांच वर्षों में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने देश को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से भारत का लौटना बहुत मुश्किल सा लगता है। इसलिए जितनी जल्दी जनता यूपीए सरकार की विदाई करने की मानसिकता बना ले, उतना ही वे देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। पांच वर्ष में यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर असफलता ही असफलता मिली है। सफलता सिर्फ एक ही चीज में मिली है कि दुर्घटनावश बनी कांग्रेसनीत सरकार ने लोकतंत्र को बलाये ताक दूर रख नोटतंत्र के बूते बचाया वहीं दागी मंत्री शिबू सोरेन (गुरूजी) को इसलिए हटाया कि उन पर हत्या का आरोप लगा था पर केंद्र में कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री कबूल कर लिया। यूपीए से गत पांच वर्षों में सबसे मजबूत समर्थक वामपंथियों ने विदा ली, टीआरएस, बसपा, वाइको ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और जिस सपा के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही कुर्सी के लिए वहां भी घुटने टेक दिए।

कांग्रेसनीत यूपीए सिद्धांतहीन, नीतिहीन और कमजोर नींव पर खड़ा गठबंधन था। अगर पिछले पांच वर्षों पर नजर दौड़ायें तो लगता है कि जितनी साख देश की सन् 1999 से लेकर 2004 तक में बढ़ी थी यूपीए सरकार ने उस साख पर पूरी तरह से बट्टा लगा दिया। एनडीए के कार्यकाल में जो स्वाभिमान की ज्योति जली थी उस भारत की स्वाभिमानी ज्योति को यूपीए सरकार ने बुझा दिया।

हाल ही के राष्ट्रपति अभिभाषण, रेल बजट, अंतरिम बजट में यूपीए ने जो कुछ परोसा है उससे लगता है कि देश न केवल मंदी की मार से गुजर रहा है बल्कि यूपीए सरकार बुद्धि की मार से भी गुजर रही है। प्रारंभ से अब तक यूपीए सरकार में विवेकहीनता का दौर चलता रहा। एनडीए ने तीन छोटे राज्यों का निर्माण किया। वह इसलिए कि इन क्षेत्रों का स्वर्णिम विकास हो। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ प्रगति के नये–नये आयाम तय कर रहा है वहीं झारखंड में प्रारंभ से ही कांग्रेसनीत यूपीए ने लोकतंत्र का गला घोंटने का षड्‌यंत्र जारी रखा, आज झारखंड की इतनी दयनीय स्थिति हो गयी है कि झारखंड के दो करोड़ से अधिक लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और मतदान तिथि की बाट जोह रहे हैं कि कब मतदान हो और कांग्रेसनीत यूपीए से देश और झारखंड को मुक्ति मिले।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तोड़ी गयी। ऐसे अनेक काम किए गए जो राष्ट्र विरोधी की संज्ञा में आ जाते हैं। बजट को सांप्रदायिक बना देना, वजीफे को मजहब से जोड़ देना, बैंकों में मजहबी आधार पर कर्ज देना, 90 जिलों के विकास की सूची मजहबी आधार पर बनाना, सच्चर कमिटी की आड़ में तुष्टिकरण की समाधि पर फूल अर्पित करना। ऐसे अनेक मसले हैं जो स्वयं दर्शाते हैं कि यूपीए सरकार के लिए संविधान

बड़ा न कानून, सबसे बड़ा उन्होंने सत्ता और कुर्सी को मान लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने देश था और आज के कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी के सिवा कुछ नहीं है। पिछले पांच वर्षों में देश के बहुसंख्यकों के आस्था वाले केंद्रों, प्रतीकों और आचार्य, धर्माचार्य, शंकराचार्य को जिस तरह से न केवल बदनाम किया गया वरन् उन्हें नष्ट करने की साजिशाना हरकत की गयी वह न केवल निंदनीय है बल्कि देशवासियों के लिए शर्मनाक है।

चतुराई और धूर्तता से न मनुष्य का जीवन चलता है, न परिवार, न समाज, न राज्य, न राष्ट्र। आज जो कुछ देश भोग रहा है उससे इस देश के वामपंथी खासकर सीपीएम–सीपीआई अपने को बरी नहीं कर सकते। खंडित जनादेश प्राप्त करने वाली कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को अपने स्वार्थों के लिए अखंड रखने का जो सिलसिला वामपंथियों ने चलाया उसे इतिहास माफ नहीं करेगा। असहाय, जीर्ण–शीर्ण टूट के द्वार पर खड़ी, ठूठ की तरह सिमटी कांग्रेस और उसके घटक को देखें तो लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी देश की बजाय परिवार की पार्टी हो गयी। सपा की हालत भी वैसी ही है। बसपा में तो एक ही सुप्रीमो और जहां तक बात राजद, लोजपा की है तो वह भी व्यक्तिवाद पर आधारित दल है। ऐसे में अनेक दल जिनका राजनीतिक अस्तित्व किसी एक या दो चार लोकसभा में है वे चुनाव के बाद गठबंधन के प्राण तत्व बन जाते हैं और फिर यहीं से शुरूआत होती है राजनीतिक कालाबाजारी। जनता को भी चाहिए कि वह अब ऐसी सरकार न बनाए जिसका हर घटक अपने मुख्य घटक से आए दिन राजनीतिक सौदेबाजी कर देश की जनता का शोषण करे।

देश आगामी चुनाव प्रमुख रूप से दो मुद्दों पर लड़ेगी – एक सफल एनडीए और असफल यूपीए गठबंधन। राजनीतिक तौर पर भारत के मर्म को समझने वाला व्यक्तित्व लालकृष्ण आडवाणी चाहिए या नाईट वाचमैन की तरह किसी के कहने पर ड्यूटी देने वाला व्यक्तित्व। फैसला इस बात का भी करना होगा कि वोटों के लिए भारत के विभाजन की चिंता किए बगैर तुष्टिकरण की बलिवेदी पर देश को चढ़ा दिया जाए या हम सब ''एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र'' को ध्येय मानकर काम करने वालों को चुनें। फैसला यह भी करना होगा कि आतंकवाद और महंगाई से मौत परोसने वाले यूपीए सरकार चाहिए या फिर विश्व में पोकरण विस्फोट कर भारत का स्वाभिमान जगानेवाला और विश्व के ताकतवर देशों की धमकी के आगे न झुकने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्ववाली एनडीए जैसी सरकार चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि देश इन चार मसलों पर सोचेगा तो उसकी अंगुली जब इवीएम मशीन पर पड़ेगी तब वह सिर्फ कमल का बटन दबाएगी और भाजपानीत सरकार बनाने में सहयोगी बनेगी और साठ वर्षीय रानजीतिक अनुभव और अनेक प्रशासनिक क्षमता से युक्त लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। ■

भूतपूर्व सैनिकों की 'एक रैंक एक पेंशन' मांग का समर्थन

Hkkजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूतपूर्व सैनिकों की 'एक रैंक एक पेंशन' की मांग पर यूपीए सरकार द्वारा दिखाई गई उपेक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि जब से वर्तमान सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है तब से भूतपूर्व सैनिक इसका घोर विरोध करते आ रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी छेड़ा है।

हर दस वर्ष बाद सशस्त्र बलों के वेतन की बढ़ोत्तरी संबंधी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से क्रमिक आयोगों के कार्यान्वयन से पहले सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा प्राप्त पेंशन के बीच का अंतर बढ़ता चला जाएगा और भविष्य में तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाएगी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे क्योंकि आज प्रत्येक सेवारत सैनिक कल भूतपूर्व सैनिक बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा का दृढ विश्वास है कि भूतपूर्व सैनिकों की 'एक रैंक एक पेंशन' संबंधी मांग, पुराने अनुभवी सैनिकों की समस्या का समाधान, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से आयोग निर्माण, युद्ध में विकलांग सैनिकों को मुआवजा और निर्धारित समय से पूर्व सेवानिवृत्ति जैसे मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार उन भूतपूर्व सैनिकों की पीड़ा को समझती नहीं है जबकि उन्हें अब अपने अमूल्य मैडलों को लौटाने पर मजबूर होना पड़ा है, जिन्हें उन्होंने देश की सेवा करते हुए अर्जित किया था।

श्री सिंह ने कहा कि भाजपा देश के भूतपूर्व सैनिकों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है और उन्हें विश्वास दिलाना चाहती है कि पार्टी एनडीए के घोषणा पत्र में 'एक रैंक एक पेंशन' की मांग को शामिल करने पर गंभीरता से विचार करेगी और केंद्र में सत्ता में आने पर शीघ्र से शीघ्र संतोषजनक हल निकालेगी। ■

'राष्ट्रपति अभिभाषण' पर चर्चा

गत 12 फरवरी, 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने संसद सत्र की संयुक्त बैठक में 'अभिभाषण' प्रस्तुत किया। संसद के दोनों सदनों में 'राष्ट्रपति अभिभाषण' पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों ने अपने प्रभावशाली भाषणों से संप्रग सरकार की 'उपलब्धियों' की पोल खोल दी। हम यहां लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री थावरचंद गहलोत तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री जसवंत सिंह, श्री अरुण जेटली, श्री प्रभात झा के भाषणों का संपादित अंश प्रस्तुत कर रहे हैं:

सही समय पर लोग उस 'हाथ' को पहचानेंगे : आडवाणी

पिछला सत्र जब हुआ था तो आरंभ की सारी चर्चा मुम्बई पर केन्द्रित थी, क्योंकि मुम्बई की घटना तब घटी ही थी और सरकार ने मुम्बई की घटना के बाद देश को कहा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशेष कानून लायेंगे। मुम्बई के बाद ही क्यों उससे पूर्व के पांच सालों में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जब हम कहते थे कि कम से कम कानूनी ढांचा तो ऐसा हो कि आतंकवादियों को दंडित किया जा सके तो सरकार का कहना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान कानून इसके लिए पर्याप्त है। सरकार ने ऐसा कानून नहीं बनाया लेकिन एन.डी.ए. ने जो कानून बनाया था उसको निरस्त कर दिया और गर्वित होकर कहा कि हमने पोटा निरस्त कर दिया है। जब आप आतंकवादरोधी कानून लेकर आए तो पूरे एन.डी.ऐने इसका समर्थन किया। किन्तु इस कानून के कारण कसाब के कन्फेशन का उपयोग तक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। इसलिए, उस पर मकोका के अधीन अभियोजना चलाया जा रहा है क्योंकि मकोका के अंतर्गत उसका कन्फेशन ग्राह्य साक्ष्य है।

यदि ऐसी स्थिति है तो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में किया गया संशोधन कितना दोषपूर्ण है। इसलिए, हमें यह स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिए कि आतंकवाद के मामले में यह विशेष संशोधन आवश्यक है और हम इस संशोधन को करेंगे। उस समय जब हमने कहा था कि इस कानून को स्थायी समिति को भेजा जाए तो तब गृहमंत्री ने कहा कि हम करैक्शन्स करेंगे, जो कमियां होंगी उन्हें दूर करेंगे। इस बार वे कोई संशोधन नहीं लाए हैं। 26/11 के कांड की पूरी जांच होनी चाहिए और उसमें रामपुर के सी.आर.पी.एफ. कैम्प पर हमला और उसके साथियों की भी जांच होनी चाहिए। यदि उनके कोई समर्थक थे तो उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अफजल गुरू और बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में अगर कोई फैसला किया है तो कोई कारण नहीं है कि सरकार उसका आदर न करे। उच्चतम न्यायालय ने बांग्लादेश से इन्फिलिट्रेशन, इल्लीगल इमीग्रेशन के बारे में कहा कि यह बाहय आक्रमण से कम नहीं है। सरकार की इसमें सांठगांठ है। यह सं.प्र.ग. सरकार की गंभीर भर्त्सना है और यह देखकर हैरानी होती है कि इसके बाद सरकार ने क्या किया है। इस भर्त्सना को सही परिप्रेक्ष्य में लेने और सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय उन्होंने फॉरेनर्स एक्ट में संशोधन किया और उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम में किए गए संशोधन को भी रद्द किया है। सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह देश के लिए बहुत घातक है। कश्मीर के सवाल को हम यू.एन. में ले गए जिसका परिणाम हमें 60 साल तक भुगतना पड रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि असम में, पूर्वी भारत में जो लगातार इनफिलट्रेशन, इल्लीगल इमीग्रेशन हो रहा है, उसके कारण देश विभाजन का एक दूसरा खतरा पैदा हो रहा है। कश्मीर की समस्या कोई है तो वह आक्रमण है। उन्होंने 1947 में आक्रमण किया। कश्मीर के बारे में जो भारत का दृष्टिकोण है, वह इस सदन में सर्वसम्मत् प्रस्ताव द्वारा पारित किया हुआ है और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि जो हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में आक्रमण करके लिया, वह हिस्सा वास्तव में भारत का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्मप्रशंसा बहुत की गयी है। वस्तुस्थिति यह है कि इस समय हम गंभीर आर्थिक संकट में हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी का नाम लेकर हम चुनकर यहां आए हैं। कल बजट प्रस्तुत करते हुए सदन के नेता ने यह बात कही थी कि आम आदमी का हम भला करेंगे। इन्फलेशन खत्म हो गयी, कंट्रोल हो गयी, लेकिन इन्फलेशन कम हुई है तेल और कुछ अन्य चीजों के दामों में कमी आने के कारण। जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो आम आदमी को चाहिए विशेषकर खाद्य पदार्थ, उनकी कीमतें लगातार बढ़ी हैं। एक और संकट है जिन लोगों के पास रोजगार है उनका रोजगार चला जाना। बेरोजगारी पहले से ही बहुत है उसके ऊपर जिनके पास रोजगार है, उनका रोजगार चला जाना बहुत भयंकर मामला है। जहां तक किसानों का प्रश्न है तो सरकार उनके जीवन की भी रक्षा नहीं कर सकी। हजारों की संख्या में लोग आत्महत्या करें, दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं हुआ।

कीमतें बढ़ें और किसानों को फायदा हो, यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, प्रबंधन ऐसा

है कि व्यापारी को थोड़ा बहुत फायदा होता है, किसानों को नहीं होता। जिन्होंने आत्महत्या की, उन सबने बैंकों से पैसा नहीं लिया था। उनके परिवारों की स्थिति वैसी की वैसी ही है। स्वतंत्र भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति के लिए सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट बना और वह बना एन॰डी॰ए॰ सरकार के समय में। उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरा हिस्सा था नार्थ–साउथ, ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर। इनमें से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा बहुत काम अभी भी हुआ, लेकिन नार्थ–साउथ, ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर में प्रगति कार्य नहीं हुआ और उसकी दयनीय हालत हो गयी। मेरा सरकार पर आरोप है कि एक बड़ा करण यह है कि बड़ी–बड़ी स्कीम्स से पैसा कमाया जाता है और इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सारा काम अटका हुआ है। गांव के विस्तार की बात की गयी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई प्रगति दिखायी नहीं देती है। खुशी की बात है कि हमारी सेना गैर राजनीतिक है। पर सामान्यतः संस्थाओं को कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को वास्तव में स्वतंत्र बनाया और किसी सरकार ने चुनाव आयोग की आथोरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की। मैं सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया सी॰बी॰आई॰ इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीटयूशन्स को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश न करें।

यूपीए के अनेक फैसले संविधान की भावना के खिलाफ : थावरचन्द गहलोत

मैं सदन के नेता प्रतिपक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो प्रभावी विचार व्यक्त किये, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। इन चार–पांच वर्षों में जिस प्रकार से यूपीए सरकार से संबंधित विचारों को न रखने वाली सरकारों को अनेक प्रकार के गलत तरीके अपनाकर के गिराने का काम किया गया है, वह निंदनीय है। उसका उदाहरण झारखंड और गोवा है। यूपीए की सरकार में प्रजातंत्र को आघात पहुंचाने वाले एक नहीं अनेक कृत्य किये गये हैं। कर्ज माफी की बहुत चर्चा की गयी है। पर इससे उन किसानों को उसका लाभ नहीं मिला है जो दो हेक्टेयर से ज्यादा भूमि रखते हैं। यह किसानों के साथ अन्याय है। किसान जिस प्रकार से परेशान हो रहा है और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो स्थायी ल खोजना चाहिए, उसे खोजने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू करनी चाहिए। सरकारी कर्ज को तो सरकार माफ कर भी सकती है, लेकिन साहूकारों से जो कर्ज लिया जाता है, वह माफ नहीं होता है। इस कारण किसान परेशान रहता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।

इसके साथ ही साथ किसान को चार प्रतिशत दर पर कृषि ऋण देना चाहिए। लेकिन यह कोशिश भी इस सरकार ने नहीं की है। सर्व शिक्षा अभियान योजना में भी इन्होंने ढ़िलाई बरती और जिस तेज गति से सर्व शिक्षा अभियान पर अमल करना चाहिए, वह नहीं किया गया है। वह सब करने की आवश्यकता है। यूपीए की सरकार में एससी एवं एसटी के हितों के खिलाफ काम किये जा रहे हैं। राज्य सभा में एक बिल पास हुआ है, वह भी एससीएसटी वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ है। देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है जबकि भारत का संविधान कहता है कि किसी जाति, धर्म के आधार पर बजट के पैसे का आवंटन नहीं होगा।

फिर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्य योजना, बजट में विशेष प्रावधान, यह भी संविधान की भावना के खिलाफ है। अल्पसंख्यक ईसाई हो, अल्पसंख्यक आप भी हैं, उसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं और उन सब लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं अच्छा होता देश के प्रधान मंत्री अगर यह कहते कि इस देश के बजट पर पहला हक उन गरीब लोगों और उन शोषित लोगों का है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करते हैं या उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का है जो मध्यम श्रेणी और गरीब परिवार के लोग हैं।

हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण या अन्य प्रकार की भेदभावपूर्ण नीतियां लागू करने का प्रावधान नहीं है। इस सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, यह निन्दनीय है। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके आंकड़े कुछ कहते हैं, रेल मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके आंकड़े कुछ कहते हैं।

इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, वह सत्यता से परे है। शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय और सस्ता न्याय की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और कदम उठाने की कोशिश भी नहीं की। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यह सरकार वहां उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देश में अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद चलाने वाली संस्थाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग, संरक्षण और समर्थन दिया जाता है। कोर्ट फैसला देता है कि श्राइन बोर्ड को अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन दे दी जाए लेकिन ये नहीं मानते हैं। कोर्ट फैसला देता है कि अफजल खान को फांसी दी जाए लेकिन वे नहीं देते हैं। कोर्ट स्टे का ऑर्डर देता है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाए लेकिन ये नहीं मानते हैं और षडयंत्र करके तोड़ने का काम करते हैं।

ये सब भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश है। महिलाओं के आरक्षण का क्या हुआ? हमारी सरकार आएगी और हम उसे करके दिखाएंगे। इस देश में जब जब कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आती है तो मंहगाई बढ़ती है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। औद्योगिक ईकाइयां रुग्णता की ओर बढ़ रही हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एन डी ए की सरकार ने तय किया था कि राज्य में मिनी एम्स की स्थापना की जाए। आठ–दस राज्यों में मिनी एम्स की स्वीकृति दी गई थी। इस सरकार ने उन सब योजनाओं पर एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया है। यह घोर निन्दनीय है। ■

राज्यसभा

राष्ट्रपति अभिभाषण मात्र एक रस्म अदायगी : जसवंत सिंह

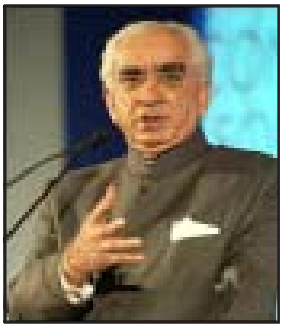

मुझे 30 से ज्यादा बार राष्ट्रपति अभिभाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हर अभिभाषण पर तो नहीं बोला परन्तु सब पर करीब–करीब बोलने का मौका मिला। राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत लम्बा था। शायद इतना लम्बा भाषण मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वास्तव में अपने आप में इस भाषण का दूसरा रिकार्ड है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत लंबा था और इसके अंग्रेजी पाठ में ऐसे कई वाक्य और शब्द दिए गए हैं जो कि समझ में नहीं आए। 'डायसपोरा' प्रवासी भारतीयों के लिए कहना बिल्कुल अनुचित है। मुझे इस सबको पढ़कर और सुनकर लगा कि यह जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, यह अपने आप में एक सूखी–अनमनी सी रस्म अदायगी है। दुख होता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक रस्म अदायगी क्यों रह गई!

मैं तीन–चार मसलों पर ही अपनी बात रखूंगा। हम सुरक्षा को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के रूप में विभाजित करते हैं, यह विभाज्य नहीं है। इसका बंटवारा हो नहीं सकता, परन्तु हम करते हैं। यह एक वृहद् प्रश्न है, इस पर सभी को मिल कर विचार करने की आवश्यकता है।

नवम्बर में मुम्बई में जो हादसा हुआ, उसके बारे में कहना चाहूंगा। मैं सरकार के विरूद्ध आलोचना नहीं कर रहा हूं; यह व्यवस्था के कार्यकरण के विरूद्ध कोई टिप्पणी या आलोचना भी नहीं है। यह एक वास्तविकता है जिसका सामना सभी लोकतांत्रिक सरकारें कर रही हैं। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने जांच शुरू की। परन्तु यहां सरकार बताए कि लगभग 70 घंटे तक कार्रवाई और विचारशून्यता क्यों रही?

पाकिस्तान पहेलियां बुझने लगा है। हमारे पास पाकिस्तान को बताने का यह पर्याप्त आधार था कि आपने यह गलत किया है, परन्तु पाकिस्तान ने पहेली की तरह इसे हमारे साथ एक प्रश्नोत्तर सत्र के रूप में बदल दिया है। जिस तरह प्रश्नोत्तर खेमे बन रहे हैं, पहली बात, मुझे यह अनुचित लगता है; दूसरी बात, यह अपर्याप्त है और तीसरी बात, उन्हें यह अनिवार्य रूप से बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक–दो चीजों का अनुरोध करना चाहूंगा। पहली बात 1993 से लेकर आज तक ऐसे कितने हादसे हुए और उनमें से कितने लोगों को आज तक सजा मिली है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। परन्तु अभी तक इस मामले का हल नहीं निकला। मैं इस विशिष्ट बिन्दु पर यह अनुरोध करता हूं कि आसूचना और स्थानीय प्रशासन की विफलता के बारे में जांच के आदेश दें।

अगला मुद्दा सशस्त्र सेनाओं से संबंधित है। उसमें मैं दो–तीन बुनियादी बातें आपसे अर्ज करूंगा। यह अत्यंत जटिल प्रश्न है कि कोई नागरिक मरने के लिए क्यों तैयार होता है? उसके पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें अन्य कारणो के अलावा नैतिक आधार, इज्जत, इकबाल, सशस्त्र सेनाओं की प्रतिष्ठा शामिल है। दूसरी प्रश्न विशिष्टता, वर्दी का अंतर और देश के संबंधित सुरक्षा संगठनों के अधिकारों और कर्त्तव्यों से संबंधित है। एक व्यक्ति, जो इज्जत भारत गणतंत्र की वर्दी पहन के पाता है, वह अपने आप में विशिष्ट है। आजकल कंपनियों के दरबानों को फौज की वर्दियां की नकल करते देखा गया है, जो कि वही मेडल लगाते हैं। इस बारे में कानून बनना चाहिए। कृपया किसी भी संगठन को सेना की तरह सैन्य वर्दी पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। कृपया इसका समाधान कीजिए।

अगला मामला भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में है। आज भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। वे 6वें वेतन आयोग द्वारा सृजित विभिन्न विषमताओं से त्रस्त हैं। इस संबंध में विभिन्न स्पष्टीकरण जो कि रक्षा लेखा नियंत्रक के पत्रों द्वारा भेजी जा रही है, उससे और भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि किस तरह एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर की पेंशन उनसे आधी से भी कम सेवा के रैंक वाले लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर हो जायेगी। यदि आप चाहते हैं कि सशस्त्र सेनाएं अच्छे से अच्छे कार्य करे तो आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। एक रैंक एक पेंशन का प्रश्न काफी समय से लंबित है। मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि जो अधिकारी और व्यक्ति एक बार वर्दी में थे, वे अपने मेडल वापस करने या धरने पर बैठने के लिए किस तरह मजबूर हैं। जब संसद सदस्यों के रूप में हमने अपने को वह दिया है जो एक रैंक एक पेंशन के समान है तो आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसे इंकार कैसे कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पास बिना रोजगार के अथवा सीमित रोजगार के उपलब्ध अवसरों के साथ आगे पूरा जीवन होता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस एक रैंक एक पेंशन के जटिल प्रश्न का समाधान करें और सुनिश्चित करें कि सेना और भूतपूर्व सैनिकों को वेतन, भत्तों अथवा पेंशन के कारण परेशानी न भुगतनी पड़े।

हमारे पास परमाणु तकनीक है और हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि हमें उस मामले में निर्णय लेने की स्वायत्तता बनाई रखनी चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उसके सचिव दोनों ने ही परमाणु मुक्त विश्व बनाए जाने की नीति का पालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसमें वर्ष 2010 में परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा करना तथा व्यापक परमाणु अप्रसार संधि को फिर से बहाना किए जाने की संभावना शामिल है। इसलिए, हमारे पास पर्याप्त रूप से सक्षम वैज्ञानिक अवसंरचना होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार तथा महत्वपूर्ण परमाणु हथियार क्षमता के मामले में

किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए शासन तथा बजटीय संसाधनों में प्रमुख रूप से समायोजन किए जाने की जरूरत है।

हमारे पड़ोसी देशों में इतनी अशांति पहले कभी नहीं रही जितनी कि आज है। अपने पड़ोसी देशों में जिस समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है, वह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियों के विफल रहने का परिणाम है। अमेरिका के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं और हमारे सामने सही और बराबर के संतुलन कायम करने की चुनौती मौजूद है।

मैंने स्वयं का एक सिद्धांत विकसित किया है कि इस उपमहाद्वीप में हिमालय से लेकर महासागर तक एक प्राकृतिक संतुलन कायम है और किसी विदेशी तत्व की उपस्थिति मात्र से ही यह प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। आज, हमारे उपमहाद्वीप दो ऐसे तत्व मौजूद हैं। एक तो है नाटो–अमेरिकी उपसमिति और इसके साथ ही हमारे पूर्वी भाग में चीन जनवादी गणराज्य है। सोवियत संघ के अफगानिस्तान में घुस आने के समय बिल्कुल यही स्थिति थी। मुझे यह देखकर बड़ी निराशा होती है कि हमारा दृष्टिकोण और रवैया उसी प्रकार से दबा हुआ है जैसा कि 1979–80 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर किए गए हमले के दौरान था।

माननीय रक्षा मंत्री ने आधुनिकीकरण में विलंब होने के लिए सरकारी नौकरशाही को दोषी ठहराया है। आवंटन की समस्या नहीं है, बल्कि मुद्दा समय पर समुचित ढंग से उसे कार्यान्वित किए जाने का है। हमारी विदेश नीति में एक प्रकार की निष्क्रियता व्याप्त हो गयी है और हमें कई पीढ़ियों तक इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे जैसा कि पाकिस्तान और चीन के मामले में पंडित नेहरू द्वारा लिये गए निर्णयों का परिणाम हमें झेलना पड़ रहा है। आंतरिक नीतियों में हुई गलतियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में की गई गलती को सुधारना आसान नहीं होता।

आज नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल के बीरगंज में एक मधेशी जनाधिकार मोर्चा का गठन किया गया है और मोर्चा के सम्मेलन में पहली बार चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हुआ है। नेपाल के मधेशी क्षेत्रों में माओवादियों द्वारा विद्रोह किया जा रहा है।

अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के फाटा और बलूची क्षेत्रों में तालिबान, हिकमतयार और हकानीन का प्रभाव धीरे–धीरे फैल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका वहां से 8500 मील दूर है। हमारे यहां की वहां से दूरी महज साढ़े आठ मिनट में तय हो सकती है। तालिबानी विद्रोह कम नहीं हो रहा है। यह फैल रहा है।

चीन जनवादी गणराज्य द्वारा जारी रक्षा संबंधी श्वेत पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि दूसरे देशों में अपनी राजनीतिक, कुटनीतिक और आर्थिक हितों पर भी निगरानी रखनी है। राजनीतिक अर्थों में इसका प्रभाव दूसरे देशों की सरकारों पर भी देखने को मिलेगा जैसा कि आज वह उत्साहपूर्वक नेपाल और पाकिस्तान में कर रहा है। नंनजिंग आर्मी कमांड कॉलेज के उप प्राचार्य ने कहा है कि परमाणु हथियार का पहले प्रयोग नहीं करने की नीति असीमित नहीं है। हमें इस मामले के साथ ही जल संबंधी मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि सतलुज नदी के समान ही ब्रह्मपुत्र और टी–सांगपो नदी की स्थिति बिगड़ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर आज खतरा मौजूद हो गया है। इसमें 30 मीटर का खड्डा पड़ता जा रहा है और 20 किलोमीटर की दूरी तक 1000 मीटर क्षेत्र में इसका क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है और उसी क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है और यदि ब्रह्मपुत्र का पानी उस बांध के अंदर रोक लिया जाए तो हमारे देश की स्थिति पर कितना खराब प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में पानी की कमी मौजूद है, हम ब्रह्मपुत्र का पानी को नहीं खो सकते जैसा कि पहले सतलुज के पूर्वी भाग के मामले में हो चुका है।

संकट में है राष्ट्रीय सुरक्षा व अर्थव्यवस्था : अरुण जेटली

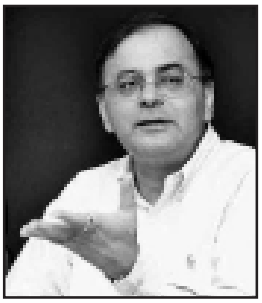

राष्ट्रपति का अभिभाषण एक ऐसा प्रारूप है जिसे सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और अत्यधिक सम्मानित संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति सरकार के प्रारूप को पढ़ने का कार्य करते हैं। उन सभी कार्यक्रमों का समुच्चयन राष्ट्रपति का अभिभाषण बनता है।

हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा संकट में है। आज हम कहीं ज्यादा ऋण में डूबे हुए राष्ट्र हैं जितना हम पहले कभी नहीं थे और हम कहीं ज्यादा असुरक्षित राष्ट्र हैं जितने हम पहले कभी नहीं थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संकट से उबरने हेतु दिशा–निर्देश और बल का पूरी तरह अभाव है। संप्रग ने इस तरीके से कार्य किया है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होना चाहिए, वह संसद के प्रति संवैधानिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए, वह नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहा है। किसी नेता से राष्ट्र के नेतृत्व की उपेक्षा की जाती है, नेतृत्व निर्णय लेने की एक कला है न कि टिके रहने की कला ताकि आप निर्णय लेने से परहेज करें और आप अपने समूहों अथवा सहभागियों को अपना विरोधी न बनाएं और इस प्रकार टिके रहने में कामयाब रहें। संप्रग चुनाव के बाद का गठबंधन था और चुनाव के बाद के गठबंधन के कार्य करने का एक कारण यह था कि भाजपा और राजग को सत्ता से बाहर रखा जाए। अतः विभिन्न असमान समूह सरकार में शामिल हो गये और कुछ ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस सरकार ने दो चरणों में कार्य किया। पहला साढ़े चार साल का चरण सरकार के लिए परेशानी का चरण था जिसमें वह महत्वपूर्ण निर्णय करने में अक्षम थी क्योंकि जो समूह बाहर से समर्थन दे रहे थे वे उन निर्णयों से सहमत नहीं थे। ऐसे में विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र का कार्य कैसे चल सकता है जब सत्ताधारी दल ने यह निर्णय लिया हो कि दल में उसकी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर उसका अंतिम लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में वरीयता प्राप्त

परिवार के वारिस को पेश करना है और प्रधान मंत्री केवल एक कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में होगा? प्रचार की प्रकृति से इसका पता चलता है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करने के लिए अपने अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार जता सकता है, जिसकी जनतंत्र में आवश्यकता होती है। इस संकट के समय में हमें दृढ़ निश्चयी नेतृत्व की आवश्यकता है। हमें निर्णय लेने में सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। मुझे गठबंधन सरकार की सीमाओं की जानकारी है। गठबंधन सरकार को देश को उसके समक्ष उत्पन्न संकट से उबारने के लिए अवश्य कदम उठाने चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है उसकी क्या स्थिति है। पिछले पांच वर्षों ने भारत के नर्म राष्ट्र होने के विचार को मजबूती प्रदान की है। पिछले दो दशकों में हमारे ऊपर आतंकी हमले हुए थे और पिछले से दशकों के अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि अमेरिका के विपरीत जहां 9/11 के बाद वास्तव में आतंक के विरूद्ध लड़ाई शुरू हुई थी, भारत की लड़ाई कहीं पहले आरंभ हो जानी चाहिए थी और आतंक का मुकाबला करने हेतु कठोर देश बनना चाहिए था।

हमने यह अभियान चलाया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सुरक्षा के विचार के साथ जोड़ा जाना चाहिए और हम अपेक्षित व्यावसायिक सलाह के अनुसार चलें अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को अब वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जाए? जब चुनाव हुए थे तो हम छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में माओवादियों के साथ बैठे थे और उनके साथ कार्य किया था। हाल ही की रिपोर्टों से पता चलता है कि झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो उप–चुनाव हार गए थे उन्होंने उप–चुनाव जीतने के लिए माओवादियों से हाथ मिला लिया था। हमने आतंकवाद के विरूद्ध अपनी लड़ाई को हल्का बना दिया है और हमने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया है। ऐसे आतंकवादी समूह हैं जो धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित हैं और कुछ उससे प्रेरित नहीं हैं परन्तु जो बात समान है वह यह है कि आतंकवाद का प्रभाव अंततः धार्मिक रूप से निष्पक्ष है। आतंकवाद भारत के विचार और जड़ों पर ही प्रहार करता है। जो कुछ हुआ है, हमें ईमानदारी से उसका विश्लेषण करना चाहिए। 26/11 के मुंबई हमले के बाद प्रत्येक आसूचना अभिकरण जिम्मेदारी और दोष दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहा था। महीनों और वर्षों तक मामले अनसुलझे रहे। लोग मारे गये और आतंकवादी भाग गए। वे कहीं पर भी बम रख देते थे और हमला कर देते थे। सुरक्षा प्रतिक्रियाएं कमजोर थीं। हमें संसद को नहीं भूलना चाहिए। हम सभी सुरक्षित थे क्योंकि संसद के चारों ओर स्टाफ और पुलिस थी तथा सुरक्षा बल तेज थे। अक्षरधाम में कुछ ही घंटों में उन्होंने आतंकवादियों का सफाया कर दिया। हमारा आसूचना तंत्र कमजोर हो गया था, साढ़े चार वर्षों तक हमारी स्थिति दयनीय थी। हमने एक तर्क दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए किन्हीं विशेष कानूनों की जरूरत नहीं है। आपने साढ़े चार वर्षों तक देश को गुमराह किया और कहा किसी विशेष कानून की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 26/11 के बाद हमारी विदेश नीति उपलब्धि महान रही है।

तालिबान आज हमारे दरवाजे पर है। हम सभी यह भेद करते रहे हैं और विदेश नीति की सफलता का दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान में तालिबान, आईएसआई और सेना अलग–अलग हैं। आज पाकिस्तानी क्षेत्र के भाग तालिबानी नियंत्रण में आ रहे हैं। तालिबान भौगोलिक सीमाओं का सम्मान करने वाला नहीं है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि तालिबान का सारा विचार भारतीय राज्य के खिलाफ है। तालिबान पांच घंटे की दूसरी पर हो सकता है। परन्तु, विचारधाराएं बड़ी तेजी के साथ भौगोलीय सीमाएं पार करती हैं। इसलिए, 'संप्रग' सरकार को यह समझना चाहिए कि इस विचारधारा को दूर रखना है क्योंकि यह भारत के सिद्धांत के विरूद्ध है। जब अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जमीन का विवाद हुआ था और संघर्ष समिति कह रही थी कि यात्रियों को उनकी मूल सुविधाओं के लिए जमीन क्यों नहीं मिलती है तो उस समय यह विचार क्यों नहीं आया कि उनको जमीन दी जानी चाहिए। यदि आप जमीन देते हैं तो अलगाववादी नाराज हो जाते हैं और प्रति आंदोलन शुय कर देते हैं। सरकार और विशेष रूप से प्रणब मुखर्जी ने इस सुझाव में कुछ समझदारी देखी और समाधान को स्वीकार कर लिया। जब आप पाकिस्तान पर यह कहते हुए निर्भर है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि इस षड़यंत्र की योजना आपके देश में बनाई गई थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विदेशों में अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो पाकिस्तान को खुश रखना चाहती हैं क्योंकि पाकिस्तान उनको इस क्षेत्र मे एक सुविधाजनक आधार प्रदान करता है। भारत सरकार की विदेश नीति की पहल यह थी कि कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण से यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची से हटना चाहिए और इसमें सीमापार आतंकवाद को वापस लाया जाना चाहिए। ब्रिटिश विदेश सचिव भारत आते हैं और यह कहते हैं कि यदि आप सीमापार आतंकवाद के मामले और 26/11 जैसी घटनाओं को हल करना चाहते हैं तो इसका मूल कारण हल किया जाना चाहिए और मूल कारण कश्मीर है।

हमने अभी भी सबक नहीं सीखा है आन्ध्र सरकार चुनाव से पूर्व माओवादियों के साथ युद्धविराम करेगी। हूजी ने बंगलादेश को अपना आधार बना लिया है। यह आईएसआई और अलकायदा का एक संगठन है। हम 20 मिलियन घुसपैठियों, जो अवैध रूप से हमारे देश में आ गये हैं, से चिंतित नहीं हैं। बिहार, बंगाल और असम में ये घुसपैठिएं भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। परन्तु, वे एक सुविधाजनक वोट बैंक हो सकते हैं। 'संप्रग' सरकार को 8.4 प्रतिशत विकास दर की समृद्ध अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी और जब इसका कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है तो इसने देश को ऋणग्रस्तता में छोड़ दिया है आज आपके पास 230 मिलियन टन की अत्यधिक फसल हुई है। वैश्विक खाद्य कीमतें कम हुई हैं इसलिए, तार्किक रूप से खाद्य कीमतें भी कम होनी चाहिए थी। परन्तु भारत में खाद्य कीमतें अभी भी 11 प्रतिशत और मुद्रास्फीति अलग से है। 2007 में अमरीका में ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए थे कि वैश्विक मंदी आ सकती है। मंदी का पहला संकेत यह था कि अमरीका में आधा मुख्य संकट हो सकता है। दूसरे, संकट का संकेत यह था कि आपके कुछ वित्तीय संस्थान धराशायी हो सकते हैं। आपसे बाजार से सारी तरलता सोख ली है। मंदी आपके दरवाजे पर थी। कीमतें कम हुई और उपभोक्ता के पास खरीदने के

लिए कोई धन नहीं रहा। आपके निवेश समाप्त हो रहे थे और आपके किसन दुखद स्थिति में थे। आज, अभी भी किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं और आप सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं।

जब 'राजग' सत्ता में थी तो इसका मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग थे। स्वर्णिम चर्तुभुज योजना के ठेके 'राजग' द्वारा दिए गए थे। उस समय जनरल खण्डूरी मंत्री थे और 97.40 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था। ग्रामीण सड़कों में भी आपको ऐसी ही स्थिति का पता चलेगा। एनआरईजीए में 14 प्रतिशत लोगों को 100 दिन का वेतन अथवा वृतिका मिली है। जब पाकिस्तान की एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत आयी थी तो श्री आडवाणी ने उनसे पूछा था कि भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है कि पिछले 100 साल में हम एक लोकतंत्र के रूप में फले फूले और आप एक लोकतंत्र के रूप में समाप्त हो गये। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि तीन गलतियां हैं जो हमने की और आपने नहीं की और वह तीन गलतियां हैंः आपके पास एक व्यावसायिक सशस्त्र सेना है लेकिन हमारे पास एक सशस्त्र सेना है जिसकी राजनैतिक इच्छाशक्ति है। दूसरी बात आपके न्यायाधीशों ने कभी भी सरकार का निवेश नहीं माना। तीसरी बात आपका निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों से धोखा नहीं दिया। यदि आपके देश में ये तीनों संस्थाएं सुरक्षित नहीं होती तो शायद हम भी आपकी तरह से होते। इन्हीं गंभीर चुनौतियों के साथ 'संप्रग' सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। हमने सोचा था कि एक प्रेरणादायक नेतृत्व इस देश का नेतृत्व करेगा। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज हमें क्या मिला। प्रत्येक मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यक्रमों की मात्र एक सूची प्रेरणादायक नहीं होती। यह देश के लिए मार्गदर्शक नहीं है।

यथार्थ से दूर है अभिभाषण : प्रभात झा

मेरे दल के नेता ने कल कहा था कि उन्होंने अपने 30 वर्षों के संसदीय जीवन में 30 बार राष्टपति जी का अभिभाषण सुना, लेकिन इतना लम्बा और उबाऊ भाषण उन्होंने कभी नहीं सुना। हमें तो पहली बार सुनने का मौका मिला था। इतने लम्बे–चौड़े भाषण में यथार्थ से दूर बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने पहले भाग में देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं, जो कि देनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें अगर एक बात और आ जाती तो राजनीति में जो बौनापन आ गया है, राजनीति में जो छोटापन आ गया है, शायद वह दूर होता और भारतीय राजनीति में जो संकीर्णता आ गई है, वह लोगों की समझ में आती। अगर उसमें एक लाइन यह भी लिखी जाती कि भारत माता का एक लाल, पूर्व प्रधानमंत्री, जो इस सदन का नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वह भी बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य की भी कामना की जाती तो मुझे लगता है कि राजनीति में शायद एक नया मोड़ आता और लोग कहते कि यह उदारता की राजनीति है।

दूसरी पंक्ति में देश के सैनिकों को, सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया गया है, अभिवादन किया गया है। मेरा मानना है कि यह सरकार नैतिक बल खो चुकी है, उसे ऐसा करने का धन्यवाद करने का, अभिवादन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस शासन में दो बार सुरक्षा बलों के परिजनों का और सुरक्षा बलों को अपने मैडल वापिस करने पड़ रहे हैं! आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आपके ही एक प्रश्न के उत्तर में है कि सेना में 12,000 अधिकारियों के पद खाली हैं और ऐसे समय में, जब आप पाक से वाक युद्ध कर रहे हैं, सैनिकों को असम्मान हो, तो यह सोचने का विषय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाली संतति कैसे भर्ती होगी सेना में, उसका मनोबल टूटेगा और जो सेना में लोग हैं, यदि उन्हें पदक लौटाने पड़ें, तो यह बड़े दुख की बात है। वह पदक उन्हें क्यों लौटाने पड़े, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

शिक्षा के बारे में कहा गया कि तमाम, सारे आईआईटी, आईआईएम शुरु किये जा रहे हैं। 13,34,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, अभी तक 8,08,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, 3,00,000 से अधिक शिक्षकों की आप भर्ती नहीं कर पाए हैं। कहां पर? जहां छोटे–छोटे गांव के स्कूल हैं, मास्टर हैं, वहां आप भर्ती नहीं कर पाए हैं, गांव के गांव आज शिक्षक विहीन हैं, शाला विहीन हैं।

भारतीय उद्योग संगठन, ASSOCHAM, की एक रिपोर्ट आई है, जो चौंकाने वाली है। भारत से जर्मनी, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने कितने लोग जाते हैं, पता है आपको? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,50,000 विद्यार्थी यहां से वहां पर पढ़ने जाते हैं। उन पर कितना खर्च होता है? जो 4,50,000 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए वहां जाते हैं, वे प्रतिवर्ष 48,000 करोड़ रूपए खर्च करते हैं, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका शिक्षा का बजट क्या है, बताइए? 48,000 करोड़ रूपए का धन यदि प्रति वर्ष रूक जाए तो विश्वस्तर के यहां पर 20 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं और मैंनेजमेंट का कोर्स यहां पर शुरू हो सकता है।

शिक्षा का यह हाल आपने कर दिया है। अब मैं स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। अभी तक हमने सुना था कि देश के किसान सिर्फ फसल के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि आज जो स्थिति देश में बनी है, देश की आबादी एक दशक में 16 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, लेकिन एक हजार में 66 प्रतिशत मरीज बढ़ रहे हैं। आपके अस्पतालों में कितने बिस्तर हैं? आप केवल 5 फीसदी बिस्तर बढ़ा पाते हैं, ऐसी हालत में जो 72 फीसदी किसानों की आबादी गांवों में है, वह क्या कर रही है? किसान को साहूकारों से केवल फसल के लिए कर्जा नहीं लेना है, आज वह अपने ईलाज के लिए कर्जा ले रहा है। आपको आने वाले दिनों में यह रिपोर्ट मिलेगी कि किसान सिर्फ फसल के लिए आत्महत्या नहीं करता, वह अपनी दवाई के लिए भी कर्ज लेता है और वह उस कर्ज के कारण मर रहा है।

उपसभापति जी, मुझसे कहा गया है कि 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूं, ताकि घंटी न बजानी पड़े। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बखान करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत बड़े–बड़े काम किए, तो मैं

पूछना चाहता हूं कि आप उड़ीसा में क्यों हार गए, आप जम्मू–कश्मीर में क्यों रह गए, आप महाराष्ट्र में समर्थन से सरकार क्यों चला रहे हैं, आप तमिलनाडु में क्यों हार गए.मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में 22 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उनमें से आप 17 राज्यों में हार गए हैं। बहुत अच्छी सरकार थीं आपकी, आपने बहुत अच्छी सरकारें चलाईं, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में आप जितने राज्यों में चुनाव हारे हैं, आने वाला चुनाव यह तय करेगा कि हारती हुई सरकार जिस तरह से आंकड़ों के माध्यम से लोगों को गुमराह करती है, बताती है कि हम यह प्रगति कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से यह सब कहा जाता है, ये सब बातें तय हो जाएंगी, अप्रैल और मई में चुनाव होने वाला है, अगर आप बहुत अच्छा काम करते, तो इन 22 राज्यों के चुनाव में से आप सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव नहीं जीतते, आप सभी राज्यों में चुनाव जीतते और आने वाले समय में देश यह तय करेगा।

उपसभापति जी, मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस भाषण में ''पंथ निरपेक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है और जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि सेक्यूलर का हिन्दी अनुवाद ''पंथ निरपेक्ष'' होता है, तो बड़ा बवाल खड़ा किया गया था।

मैं राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ''पंथ निरपेक्ष'' शब्द का प्रयोग किया है और आज चूंकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस शब्द को मान्यता मिली है।■

मसला गंभीर, सरकार चुप

निठारी की घटना से कोई सबक नहीं सीखा

आज के नौनिहाल देश के भविष्य हैं और ऐसे नौनिहालों का पिछले 13 महीने और 17 दिनों में (1 जनवरी 2008 से 17 फरवरी 2009) के बीच भारत की राजधानी दिल्ली से 2503 की संख्या में गायब होना स्वयं यह दर्शाता है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार के हाथ से कानून–व्यवस्था निकल चुकी है। निठारी की घटना का जिक्र करते हुए राज्यसभा में शून्य काल में सांसद प्रभात झा ने कहा कि यह देश घटनाओं से सबक नहीं लेता है, बल्कि इतनी देरी से न्याय देता है कि घटना करने वालों के हौंसले और बुलंद हो जाते हैं। केंद्र ने 'अंग प्रत्यारोपण कानून' बनाया हुआ है। बावजूद इसके छोटे–छोटे बच्चों की आंखें निकाल ली जाती हैं, किडनी निकाल ली जाती है, लीवर निकाल लिये जाते है, हड्डियां निकाल ली जाती हैं और यहां तक कि उनके खून को बेचा भी जाता है। इस हृदयविदारक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्यसभा में कहा कि जो बच्चे गायब हुए हैं उनकी असली उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच है। दिल्ली के आनंद विहार और फर्श बाजार में में लगभग 40 परिवार बच्चों के लौटने की आस में बिलख–बिलख कर रो रहे हैं।

श्री झा ने आगे कहा कि हद तो तब हो गयी जब पुलिस कमिश्नर डडवाल ने इस मसले पर पत्रकारों को कहा कि ये बच्चे प्रेम रोग में पड़ कर भागनेवाले हैं। श्री झा ने सदन में कहा कि 6 और 7 साल का बच्चा यदि प्रेम करता है तो सिर्फ अपनी मां और मां के आंचल से। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इतनी सामान्य–सी बुद्धि नहीं है कि ये छोटे–छोटे गरीब बच्चे आखिर किससे प्रेम करेंगे। ये बच्चे कोई अमीर घराने के नहीं हैं। ये बच्चे उन गरीब परिवारों के हैं जिन घरों में बच्चे ही सहारा होते हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री झा ने इस गंभीर मसले को जब उठाया तो अनेक सांसदों ने इस विषय पर अपनी सहमति जतायी। श्री झा ने आगे कहा कि इन नन्हे–मुन्हे बच्चों का अपहरण कर उन्हें रेलवे प्लेटफार्म पर भिखारी बना दिया जाता है। आंख फोड़ कर सड़कों पर भिखारी बना दिया जाता है और यह आरोप बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी ने सरेआम लगाया है। सत्यार्थी का यह भी कहना है कि यदि हमारा प्रयास नहीं होता तो 200–250 बच्चों का और अपहरण हो गया होता। ■

स्व. मोहन सिंह स्मृति सामुदायिक भवन का उद्घाटन

रचनात्मक कार्यों में जुटने से ही समाज सबल होगा

''जो करना है अभी करें हम/करने पर ही नाज करें/चाह यही है गांव हमारा/गांवों का सरताज बने'' इसी ध्येय को लेकर समाज पुनर्निर्माण कार्य में जुटा हुआ है स्व. मोहन सिंह स्मृति सेवा न्यास। गत 3 फरवरी को केसरिया (पूर्वी चंपारण) स्थित सुबैया गांव में स्व. मोहन सिंह सामुदायिक भवन का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राधामोहन सिंह, पथ निर्माण मंत्री डॉ प्रेम कुमार व सहकारिता मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से किया।

स्व. मोहन सिंह स्मृति सेवा न्यास के तत्वावधान में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अपने गांव समेत देश के महापुरूषों का स्मारक बनाना चाहिए, ताकि वैसे लोगों का आदर्श याद रखा जा सके। स्व. सिंह के याद में जो सामुदायिक भवन उनके पुत्र डॉ भुवनेश्वर सिंह एवं मंकेश्वर सिंह ने बनायी वह एक सच्ची श्रद्धांजलि है। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं जदयू जिलाध्यक्ष मो. ओबैदुल्ला ने संयुक्त रूप से की। इस कार्यक्रम में 20,000 लोग सहभागी हुए।

निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं उद्योग मंच, बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मंकेश्वर सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि स्व. मोहन सिंह स्मृति सेवा न्यास का उद्देश्य है स्वास्थ्य शिविर के आयोजन, युवकों को रचनात्मक दिशा, योग्य प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जन–जागरण। कार्यक्रम का संचालन प्रसाद रत्नेश्वर ने की एवं डा. मुनेश्वर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ■

यूपीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर डाला

वित्तरिम बजट पेश होने से इस बात की पुष्टि होती है कि यूपीए सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए वायदों को पूरा करने में बेहद विफल रही है और यह भी कि पिछले वर्षों में पेश किए गए बजटों में उसके दावे पूरी तरह से फर्जी थे, जिनके बारे में हम लगातार सरकार को चेतावनी भी देते रहे थे; और यह सरकार अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त व्यवस्था दोनों के कुप्रबंधन करने की पूर्णतः दोषी है।

श्री प्रणव मुखर्जी ने श्री पी चिदम्बरम द्वारा अपने पहले बजट में किए गए सात उद्देश्यों की सूची दी है और कहा है कि सरकार ने उन उद्देश्यों को पूरा किया है। सच तो यह है कि:

1. अर्थव्यवस्था को लगातार 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक के रास्ते पर ले जाने की बजाए इस सरकार ने अर्थव्यस्था को पर्याप्त धीमा किया है और इस धीमी गति की शुरूआत एनडीए के शासनकाल समाप्त होने के दिन से ही शुरू हो गई थी; यह धीमी गति इस सरकार की बदइंतजामी का परिणाम है–जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय संकट की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रही है।
2. जहां तक 'शिक्षा और स्वास्थ्य' का संबंध है, यूपीए ने शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर जीडीपी का 3 प्रतिशत खर्च करने का वायदा किया था। उसने शिक्षा पर राजस्व इकट्ठा करने के लिए सभी करों पर 2 प्रतिशत का उपकर लगाया था। वास्तव में, यह खर्च कहीं भी उसके वायदे के आसपास भी नहीं है। इसके अलावा जिस ढंग से पैसा खर्च हुआ, वह भी एकदम अस्पष्ट है और एनडीए सरकार द्वारा चलाया गया सर्वशिक्षा अभियान जारी रखने के अलावा इस सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ भी तो नहीं किया है।
3. लाभप्रद रोजगार पैदा करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की बात तो दूर, यह सरकार ऐसी अर्थव्यवस्था छोड़ कर जा रही है जिसमें वे लोग भी, जिन्हें अभी तक रोजगार मिला था, उनमें से भी कम से कम एक करोड़ लोगों की नौकरी नहीं रहेगी; और निवेश पूरी अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त कर रहा है।
4. जबकि सरकार का वायदा था कि वह 'न्यूनतम मजदूरी पर प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी' परंतु उसकी अपनी रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि वास्तव में केवल 14 प्रतिशत को ही रोजगार की पूर्ति हो पाई है; इसके अलावा यहां भी व्यापक भ्रष्टाचार और गबन हुआ है।
5. जहां तक 'कृषि ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बात है', कृषि विकास केवल उन्हीं दिनों में ठीक–ठाक रहा जिन दिनों अच्छी मानसून हुई – न कि किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया, बल्कि सरकार की नीतियों ने किसानों को आत्महत्याएं करने पर मजबूर किया। अकेले 2009 के 47 दिनों में विदर्भ में ही 112 किसानों ने आत्महत्याएं कर डालीं – ये वही किसान हैं जिनके बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये ही 'भारत की सफल गाथा' के नायक हैं। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बजाए दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को ही ठप्प कर डाला गया – जिसकी सच्चाई का उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की बेहद बुरी हालत में मिल जाता है; इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना पूरी होने की दर 2004–05 में 81 प्रतिशत घट कर अब मुश्किल से 50 प्रतिशत भी नहीं रह गई है।
6. यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 'राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और सुधार में तेजी लाने' का दावा तो अब सभी जानते हैं कि झूठा रहा क्योंकि वायदा किया गया था कि 2009 तक केंद्र का राजस्व घाटा समाप्त हो जाएगा ताकि सामाजिक तथा वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक निवेश प्राप्त हो सके; बल्कि अब तो वित्त मंत्री भी मानते हैं कि इस वर्ष राजस्व घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहेगा और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6 प्रतिशत तक पहुंचेगा। किंतु अब भी वित्त मंत्री अंतरिम बजट में सचाई बता नहीं रहे हैं। जनवरी 2009 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा कम से कम जीडीपी का 8 प्रतिशत होगा। हम समझते हैं कि यह अनुमान भी कहीं कम है। राजस्व में जितनी भारी कमी आई है उसे देखते हुए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 10 प्रतिशत से भी बढ़

...शेष पृष्ठ 18 पर

भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री जसवंत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यशवंत सिन्हा तथा सांसद श्री अरूण शौरी द्वारा 16 फरवरी को अंतरिम बजट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति

आंकड़ों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है यह बजट

;'kor flUgk

Vतरिम बजट को लेकर मीडिया में, खासकर दृश्य मीडिया में अनावश्यक किस्म की एक उत्तेजना थी। कई लोग एक नियमित बजट और अंतरिम बजट के बीच अंतर ही नहीं कर सके। दुनिया भर की अटकलें लगाई गईं कि आखिर अंतरिम बजट में क्या होगा। हम में से कुछ लोग जो अंतरिम बजट की सीमाओं से परिचित हैं, वे जानते थे कि ये सारी अटकलें और आकांक्षाएं अनावश्यक और भ्रामक हैं।

अंतरिम बजट आंकड़ों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें एकाध महीने के लिए सरकार चलाने के लिए एक निश्चित धनराशि पर संसद की मंजूरी भर लेनी होती है। कौल और शकधर के मुताबिक, एक अंतरिम बजट का उद्देश्य लेखानुदान होता है और इसके लिए संसद में बहस की भी जरूरत नहीं होती। यह अपने चरित्र में ही इतना सामान्य होता है कि इसे बगैर किसी बहस के पारित किया जा सकता है। जाहिर है कि इस अंतरिम बजट से निराशा होनी ही थी और इसी के लिए इस दिन बाजार को धराशायी होने से नहीं बचाया जा सका।

जिस तरह मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 1996 को एक अंतरिम बजट पेश किया था, ठीक उसी तर्ज पर यह बजट भी यूपीए सरकार की उपलब्धियों का गुणगान ही था। ठीक 1996 के अंतरिम बजट की तरह इसमें भी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है। फर्क सिर्फ यह रहा कि 1996 से उलट इस बार वित्त मंत्री के पास अपने बजट अभिभाषण में कम से कम तीन पैरा वैश्विक आर्थिक मंदी के भारत पर असर को समर्पित करने के लिए समय रहा। यह एक बिल्कुल अलग बात है कि उनकी इस श्रद्धांजलि का आखिर में कोई नतीजा नहीं निकला।

यदि मुझे अंतरिम बजट के इकलौते सबसे महत्वपूर्ण तत्व को रेखांकित करने का कहा जाए, तो मैं कहूंगा कि यह पिछले साल 28 फरवरी को पी चिदंबरम द्वारा पेश किए गए आम बजट के फर्जीवाड़े को उजागर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रणव मुखर्जी ने इस आलोचना को कुछ हल्का बनाने के लिए बजट में घाटे से जुड़े तत्वों पर अपनी समझदारी दिखाई है, लेकिन ये तथ्य इतने आम हैं कि इन्हें अब छुपाया ही नहीं जा सकता।

> ***प्रणव मुखर्जी ने अब राजकोषीय घाटे को बढ़ा कर छह फीसदी कर दिया है और राजस्व घाटा बढ़ कर जीडीपी का 4.4 फीसदी हो गया है। यह भी बहुत नीचा अनुमान है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने जनवरी, 2009 में प्रस्तुत अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का आठ फीसदी रहेगा। मेरा अपना आकलन यह कहता है कि यह 10 फीसदी से नीचे रहने नहीं जा रहा***

चिदंबरम ने 28 फरवरी के अपने बजट में मौजूदा वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी तय किया था और राजस्व घाटे को जीडीपी का एक फीसदी रखा गया था। उन्होंने दरअसल घाटे को नीचा दिखाते हुए लोगों की आंखों में महज धूल झोंकने का काम किया है। वह लगातार दावा करते रहे कि उनके पास जीडीपी के अतिरिक्त 0.5 फीसदी की राहत है, यानी अगर मौका मिले तो वह राजकोषीय घाटे को जीडीपी का तीन फीसदी भी दिखा सकते थे। इसी के दायरे में उन्होंने तमाम किस्म के व्यय को तय करने की बात कही।

प्रणव मुखर्जी ने अब राजकोषीय घाटे को बढ़ा कर छह फीसदी कर दिया है और राजस्व घाटा बढ़ कर जीडीपी का 4.4 फीसदी हो गया है। यह भी बहुत नीचा अनुमान है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने जनवरी, 2009 में प्रस्तुत अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का आठ फीसदी रहेगा। मेरा अपना आकलन यह कहता है कि यह 10 फीसदी से नीचे रहने नहीं जा रहा, यदि आप राजस्व के मोर्चे पर भारी गिरावट को संज्ञान में लेते हैं।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण पहले ही इस साल जनवरी के अंत तक के लक्ष्य के मुकाबले एक लाख करोड़ रुपए नीचे आ गया है। औद्योगिक मंदी और कच्चे तेल की कीमतों में नाटकीय गिरावट का जाहिर तौर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम शुल्क संग्रहण पर असर पड़ेगा। दोनों मिल कर जीडीपी का कम से कम तीन फीसदी रहेंगे, जबकि आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक फीसदी का अनुमान लगाया था।

परिषद ने यह भी अनुमान लगाया था कि राज्यों का मिश्रित घाटा जीडीपी का 3.5 फीसदी रहेगा। इस तरह देखा जाए तो हमारे सामने राजकोषीय घाटा जीडीपी के 13 से 14 फीसदी के आसपास दिखाई पड़ता है जो दिल

दहलाने वाला आंकड़ा है। राजीव गांधी ने भी अपने कार्यकाल में राजकोषीय घाटे से खूब छूट ली थी, लेकिन तब भी अस्सी के दशक में यह घाटा दस फीसदी से ज्यादा नहीं गया था।

इसी का नतीजा था कि 1990 और 1991 में हम संकट में घिर गए, लेकिन अब यह इतिहास का अध्याय हो चुका है।

इस भयानक आंकडेबाजी में आप वैश्विक आर्थिक संकट को जोड़ लीजिए तो निश्चित तौर पर विनाश के नुस्खे की पर्ची मुकम्मल हो जाएगी। हमारे राजकोषीय घाटे में से अधिकांश अनुत्पादक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि वित्त मंत्री मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए कोई राहत पैकेज लेकर आए होते, तो हम इस वक्त अपना विरोध दर्ज नहीं करवा रहे होते क्योंकि हम पहले से ही एक अनिश्चित दौर में जी रहे हैं।

उन्होंने इसके बजाय उल्टा ही सोचा। इस तरह मामला यह बनता है कि अगले चार महीनों के दौरान जब देश चुनावों को झेल रहा होगा, तो हमारे सामने आर्थिक संकट रोज–ब–रोज गहराता जाएगा और दुर्भाग्य से हमारे हाथों में इससे निपटने के लिए कोई औजार नहीं होगा।

यूपीए सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही कही जाएगी कि जब उसके पास मौका था, आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था, सरकार तूफान से बचने के लिए अपने तंबू तानने में लगी थी। उसके पास चार साल का एक लंबा वक्त था जब विकास की तेज रफ्तार से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो रही थी और मानसून भी मेहरबान रहा। ऐसा मौका कभी नहीं आया था जब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकता था। दुर्भाग्य ही कहेंगे, कि उन सुनहरे वर्षों को उसने गंवा दिया। यूपीए सरकार अर्थव्यवस्था को बेहद बदहाली में छोड़ कर चली जाएगी। कह सकते हैं कि इस सरकार ने पूरी तरह 'हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे' के आर्थिक दर्शन पर काम किया है।■

बजट सरकार की अक्षमता का प्रतीक

✍ v#.k tVyh

एक औसत व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी कर सकता है जब स्थितियां भी उसके अनुकूल हों। यूपीए सरकार को विरासत में एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली थी। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने वृद्धि दर को बढ़ाने की दिशा में कोई नीतिगत पहल नहीं की, बावजूद इसके निजी उद्यमिता और अच्छी फसल ने इस दर को और तेज किया। आज, जबकि स्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, सरकार की अक्षमता अपने चरम पर पहुंच चुकी है।

अंतरिम बजट दरअसल इसी अक्षमता का प्रतिबिंब है। आज बाजार गोता मार रहा है, माहौल खराब है, वैश्विक आर्थिक कसौटियां अप्रासंगिक होती जा रही हैं, राजस्व घाटा हो रहा है, बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। यह बजट यूपीए के असली चरित्र को बेनकाब करता है। सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं कर के सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाया है। यही यूपीए का असली चरित्र है। सरकार ने दिखा दिया है कि वह नकार की मानसिकता में जी रही है।

> ***यदि आखिरी नतीजों का मिलान किया जाएगा, तो हम पाएंगे कि घाटे के आंकड़े सत्यम की बैलेंस शीट की तरह दिखने लगेंगे। असामान्य स्थितियां असामान्य प्रतिक्रियाओं की मांग करती हैं। इस अर्थ में अंतरिम बजट के मौके को यूपीए सरकार ने गंवा दिया है। यूपीए को विरासत में एक तेज अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन यह जाते–जाते पूरे देश को कर्ज के बोझ तले छोड़ जाएगी।***

आर्थिक संकट के अस्तित्व और वास्तविक आर्थिक कसौटियों के प्रति यूपीए सरकार का रवैया उसके नकार को दर्शाता है। इसीलिए शायद उसके पास देने को कुछ नहीं है और सरकार खुद की ही पीठ खुजलाने में लिप्त है।

आर्थिक मंदी के दौर में सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय की अधिकतम जिम्मेदारी सरकार को ही उठानी चाहिए। इसके उलट, पिछले पांच साल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर यूपीए सरकार का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और दूरसंचार जैसे क्षेत्र ऐसे मंत्रियों के हाथों में हैं जो पूरी तरह अक्षम हैं और जिनके पास कल्पना शक्ति का अभाव है।

चारों ओर से घेर रही मंदी ने इन क्षेत्रों में और गिरावट लाई है। यह मंदी भारत में एक करोड़ नौकरियां ले सकती है, इसलिए दूसरे क्षेत्रों में रोजगार सृजन की जरूरत है। जाहिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बगैर ऐसा संभव नहीं है।

मंदी के दौर में कर की दरों को और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है। ब्याज दरों को और ज्यादा तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत है। यह भी नहीं किया गया है।

सरकार के पास भारतीय रेलवे के नेटवर्क का तेज विस्तार करने का विकल्प मौजूद था। इस पर कोई जोर नहीं दिया गया है। अर्थव्यवस्था के व्यापक परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो तस्वीर काफी निराशाजनक नजर आती है। मंदी के माहौल में भी खाद्यान्न की कीमतें काफी ज्यादा बनी हुई हैं। नौकरियां बड़े पैमाने पर जा रही हैं, निवेश का तकरीबन सफाया हो चुका है, कर संग्रहण नीचे जा रहा है और राजकोषीय घाटों के अनुमानित आंकड़े अवास्तविक हैं।

यदि आखिरी नतीजों का मिलान किया जाएगा, तो हम पाएंगे कि घाटे के आंकड़े सत्यम की बैलेंस शीट की तरह दिखने लगेंगे। असामान्य स्थितियां असामान्य प्रतिक्रियाओं की मांग करती हैं। इस अर्थ में अंतरिम बजट के मौके को यूपीए सरकार ने गंवा दिया है। यूपीए को विरासत में एक तेज अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन यह जाते–जाते पूरे देश को कर्ज के बोझ तले छोड़ जाएगी। हम वित्त मंत्री से कम से कम यह उम्मीद कर रहे थे कि वह यूपीए को एक राजनीतिक उत्प्रेरक बल देंगे। वह इसमें भी नाकाम रहे हैं। ■

घेरा डालो-डेरा डालो अभियान

भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

>kरखंड विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर राजधानी रांची में राजभवन पर भाजपा के 'घेरा डालो–डेरा डालो अभियान' के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ कर मुख्य द्वार तक पहुंचे भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी जिसमें कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास, विधायक सरयू राय समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस लाठीचार्ज में कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है।

दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए पथराव में करीब एक

हमले के खिलाफ विपक्ष ने रास से वाक आउट किया

Hkkजपा नेता यशवंत सिन्हा पर झारखंड में प्रदर्शन के दौरान हुए हमले और दुर्व्यवहार की घटना पर भाजपा सहित विपक्षी दलों ने आक्रोश जताया और दोषी व्यक्तियों को बर्खास्त किए जाने की मांग की।

बाद में सरकार के संक्षिप्त जवाब से नाखुश विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया। इस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया है।

प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सदन में विपक्ष के नेता जसवंत सिंह ने कहा कि उन्हें यह जान कर काफी दुख हुआ कि घायल यशवंत सिन्हा को एक ट्रक में लाद कर पूरे शहर में घुमाया गया जबकि उन्हें पहले प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए थी।

सदन में उपस्थित गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें घटना के ब्योरे की पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वह कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी सदस्य का विशेषाधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने के मामले में वे किसी से पीछे नहीं हैं, न रहेंगे।

विपक्षी सदस्य चिदंबरम के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए और रूद्र नारायण पाणि तो सभापति के आसन के सामने आकर अखबार की वह प्रति दिखाने लगे जिसमें यशवंत सिन्हा पर हमले की तस्वीर छपी थी। सभापति ने कहा कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया है जो सभापति के विचाराधीन है।

जसवंत सिंह ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसका सदन में कई वरिष्ठ सांसदों ने समर्थन किया। भाजपा की वरिष्ठ सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज ने विपक्ष की ओर से वाक आउट का ऐलान करते हुए कहा कि गृहमंत्री मामले को बहुत हल्के से ले रहे हैं।

उधर बाद में पार्टी प्रवक्ता सुषमा स्वराज ने संवाददाताओं से कहा कि झारखंड में चुनाव कराए जाने और विधायकों की खरीद–फरोख्त के जरिए नई सरकार के गठन की कोशिशें बंद करने संबंधी अपनी मांग को लेकर यशवंत सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और दूसरे पार्टी नेता व कार्यकर्ता राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान यशवंत सिन्हा समेत पार्टी नेताओं पर हमला किया गया जिससे सिन्हा की हड्डी टूट गई और मुंडा भी घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सरकार ने सभी संसदीय नियमों की अवमानना करते हुए संसद को इसकी सूचना नहीं दी।

श्रीमती स्वराज ने कहा मैंने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया लेकिन सभापति ने शून्यकाल में उठाने को कहा। इसके बाद सदन में विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को उठाया कि किस प्रकार यशवंत सिन्हा और दूसरे नेताओं को बुरी तरह पीटा गया और उनके अंगरक्षकों के सिर फट गए।

उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि घटना के 24 घंटे बाद भी गृहमंत्री ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर वह इस खबर को स्वीकार और नकार सकें।

श्रीमती स्वराज ने कहा कि इस मुद्दे पर एसएस अहलुवालिया ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ■

दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और वहां राष्ट्रपति शासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसी बीच राजभवन के गेट पर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे यशवंत सिन्हा, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास व सरयू राय वहां पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेंडिंग के टूटते ही वहां तैनात पुलिसकर्मी हरकत में आ गए और आदेश मिले ही उन्होंने लाठी भांजनी शुरू कर दी, लेकिन कार्यकर्ताओं का रैला इतना अधिक था कि वे मुख्य द्वारा की ओर बढ़ने लगे।

इसके बाद वहां तैनात दंडाधिकारी ने आंसू गैस के प्रयोग का आदेश दिया। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा और भाजपा कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पानी के फब्बारे का प्रयोग करते हुए घोड़े भी दौड़ाए गए। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए। रंगीन पानी के फब्बारे का भी प्रयोग किया गया, लेकिन यशवंत सिन्हा, अर्जुन मुंडा व सरयू राय ने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाया और वे आगे ही बढ़ते रहे। इसी बीच पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं रूके तो जवानों ने यशवंत सिन्हा पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। और उनके अंगरक्षकों ने उन्हें अपनी सुरक्षा घेरे में लेते हुए बचाने की कोशिश की। लाठीचार्ज में उनके अंगरक्षक रामजतन पासवान, प्रकाश कुमार आप्त, सचिव हिमांशु के सिर में चोट आई। वे खून से लथपथ हो गए। पुलिस लाठीचार्ज में अर्जुन मुंडा और विधायक सरयू राय को भी काफी चोट लगी।

यशवंत सिन्हा ने दी चुनौती

इसके बाद पुलिस कारवाई से नाराज भाजपा नेता अपने कुछ समर्थकों के साथ राजभवन के मुख्य द्वार के निकट आकर धरने पर बैठ गए। तीनों प्रमुख नेताओं के धरना पर बैठ जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे एडीएम विधि–व्यवस्था के श्रीनिवासन को यशवंत सिन्हा ने काफी खरी खोटी सुनाई और यहां तक कि उन्हें चुनौती भी दे डाली। काफी देर तक वे वहीं डटे रहे और पुलिस–प्रशासनिक अधिकारी उनसे अनुनय–विनय करते रहे। बाद में तीनों नेताओं को बलपूर्वक उठाकर कैम्प जेल ले जाया गया।

इसके थोड़ी देर बाद प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास और विधायक दिनेश शाड़ंगी व लोकनाथ महतो भी अपने कुछ समर्थकों के साथ राजभवन के मुख्य द्वार के निकट पहुंचे और उन्हें भी बलपूर्वक गिरफ्तार कर कैंप जेल ले जाया गया।

चार नंबर गेट पर भी लाठीचार्ज

इधर राजभवन के चार नंबर गेट पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया और विधायक सीपी सिंह समेत सभी कार्यकर्ताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ, राजभवन के दो नंबर गेट पर पलामू, चतरा, गढ़वा जिले से आए पार्टी कार्यकर्ता जेड हुसैन पार्क के निकट धरना पर बैठ गए और वहीं पर यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ■

लोकतंत्र बहाली के लिए जंतर-मंतर पर भाजपा का धरना

झारखंड भाजपा के नेताओं ने प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जंतर–मंतर पर धरना दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में आयोजित इस धरने को पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सह झारखंड भाजपा की प्रभारी सुषमा स्वराज और पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी संबोधित किया।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस मौके पर कांग्रेस पर झारखंड में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद–फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी इसे किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चालू सत्र में जब केन्द्र सरकार सदन में झारखंड का बजट और वहां राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन का प्रस्ताव लाएगी तो उनकी पार्टी वहां विधानसभा भंग कर चुनाव करवाने के लिए दबाव बनाएगी।

उन्होंने गत 12 फरवरी को रांची में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए बताया कि लोकसभा में झारखंड के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेश कके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है जिस पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है।

विधानसभा भंग कर झारखंड में चुनाव कराने के मांग को लेकर किए जा रहे इस प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज में पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रघुवर दास और विधायक सरयू राय समेत कई अन्य पार्टी नेता घायल हो गए थे। धरना के बाद आज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में शीघ्र चुनाव करवाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की। ■

कमल संदेश

ढोल के भीतर पोल से अधिक नहीं लालू का रेल बजट

✍ jke ukbd

संसद में पेश किया गया अंतरिम रेल बजट सुनने में अच्छा है। लगता है कि चुनावी साल में रियायतों की रेल चल गई है। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का अंदाज भी कुछ उसी तरह दिखा। बजट पर गौर करें तो यह ढोल के भीतर पोल से ज्यादा कुछ नहीं है। मुनाफे की शायरी में लालू जी कुछ इस कदर डूब गए कि संसदीय परंपरा की परवाह भी नहीं की। अंतरिम बजट को पूर्ण बजट की तरह पेश किया। बड़ी घोषणाओं से बचना था, पर वह भी कर दिया। तमाम तरह के शुल्क का भार ढो रहे रेल यात्रियों को किराए में 2 प्रतिशत रियायत का झुनझुना पकड़ा दिया। चार साल में 90 हजार करोड़ रूपए के मुनाफे से लालू जी गदगद हैं। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दे को भूल गए।

सबसे पहले यात्री किराए में की गई कटौती का ही उदाहरण लिया जा सकता है। 50 किमी तक के सफर वाले यात्रियों को किराए में एक रूपया की छूट दी गई है। एक रूपया की दर से यह किराया बीते चार साल में चार रूपए घटाया गया है। देखने में यह बड़ी रियायत लगती है। लेकिन हकीकत में यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है। लंबी दूरी की यात्रियों को भी चुनावी चासनी पिलाई गई है। सभी श्रेणी के किरायों में 2 प्रतिशत की कटौती की गई है। कितना लाभ होगा, यह तो रेल से सफर करनेवाले लोग ही जान सकते हैं। वैसे यह छूट मामूली ही है जिसका लाभ किसी को भी नहीं होने वाला। फिर भी लालू जी ढोल पीट रहे हैं। हवा कुछ ऐसी बना रहे हैं जैसे कि आम लोगों को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया गया हो।

यहां भी गौर करने वाली बात है कि रेल बजट की रियायतों का लाभ कितने लोगों को मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना 1.2 करोड़ लोग रेल से सफर करते हैं। इनमें से अकेले मुंबई की लोकल गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 65 लाख से ज्यादा है। कोलकाता में 17 लाख लोग लोकल

रेल मंत्री को सबसे ज्यादा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर देना चाहिए था। चोरी–डकैती जैसी घटनाओं से रेल यात्री पहले से ही परेशान हैं। अब तो आतंकी हमले का डर भी सता रहा है। पर हकीकत यह है कि जरूरत के बावजूद इस मुद्दे की अनदेखी की गई है। मौजूदा सरकार के रेल मंत्री के तौर पर लालू जी द्वारा पेश किए गए पहले के चार बजट पर भी गौर किया जा सकता है। सुरक्षा मसले पर बड़े–बड़े वादे किए गए हैं। सफर के दौरान रेल डिब्बों में आरपीएफ जवानों की तैनाती की बात कही गई। क्लोज सर्किट कैमरे लगाने के वायदे किए गए। लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं किया गया है।

की सवारी करते हैं। चेन्नई में लोकल यात्रियों की दैनिक संख्या आठ लाख है। इन तीनों महानगरों में रोजाना लोकल गाड़ियों से 90 लाख या इससे भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। किराया दरों में की गई कटौती का लाभ लोकल यात्रियों को मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अंतरिम रेल बजट से शिकायत जायज है। क्योंकि किराए में छूट का सीधा लाभ केवल 30 लाख यात्रियों को मिलने वाला है। दैनिक आधार पर रेल से सफर करनेवाले तीन चौथाई लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? किराए दर में की गई कटौती का लाभ हरेक यात्री को मिलना चाहिए। रेल मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए।

रेल मंत्री को सबसे ज्यादा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर देना चाहिए था। चोरी–डकैती जैसी घटनाओं से रेल यात्री पहले से ही परेशान हैं। अब तो आतंकी हमले का डर भी सता रहा है। पर हकीकत यह है कि जरूरत के बावजूद इस मुद्दे की अनदेखी की गई है। मौजूदा सरकार के रेल मंत्री के तौर पर लालू जी द्वारा पेश किए गए पहले के चार बजट पर भी गौर किया जा सकता है। सुरक्षा मसले पर बड़े–बड़े वादे किए गए हैं। सफर के दौरान रेल डिब्बों में आरपीएफ जवानों की तैनाती की बात कही गई। क्लोज सर्किट कैमरे लगाने के वायदे किए गए। लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं किया गया है।

यह अच्छी बात है कि रेल दुर्घटनाएं घटी है। रेल प्रशासन ने दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कई उपाय किए हैं। रेल सेवा के परिचालन औसत में भी सुधार हुआ है। सवाल दुर्घटनाओं में कमी का नहीं है। बड़ा प्रश्न दुर्घटना रहित सुरक्षित यात्रा का है। सुरक्षित यात्रा के प्रति यात्रियों का विश्वास जीतने का भी सवाल है। ऐसा नहीं है कि रेल सुरक्षा ओर संरक्षा से जुड़े उपाय नहीं किए गए हैं। लालू जी से पहले के रेल मंत्री भी ऐसा करते रहे हैं। लेकिन यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयास मंथर गति से ही बढ़ रहे हैं।

अंतरिम बजट पेश करते समय लालू जी ने कविता भी पढ़ी। कहा कि हाथी चाल रेल को चीता बना दिया है।

मतलब यह कि भारतीय रेल चीते की रफ्तार से दौड़ रही है। काश ऐसा होता? यह बिल्कुल खोखला दावा है। रेल नेटवर्क की पुरानी पटरियां दम तोड़ रही हैं। अधिकांश गाड़ियां 40 से 50 किमी की रफ्तार से सफर तय कर रही हैं। समय पर गाड़ियां गंतव्य तक नहीं पहुंच रही हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए पटरियों में जान डालना जरूरी है। बेजान पटरियों पर कैसे मिलेगी रफ्तार? कागजों पर रेल गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई है। इसीलिए तो मेल–एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपर फास्ट का दर्जा दे दिया गया है। रफ्तार वही है, फिर भी यात्री सुपर फास्ट शुल्क चुकाने को मजबूर हैं। बतौर रेल मंत्री लालू जी ने हमेशा यात्रियों को दूहा है। किराया दरों में कटौती का झांसा दिया है। पहले 10 रूपए में आरक्षण हो जाता था। यही शुल्क अब दो से ढाई गुना ज्यादा वसूला जा रहा है।

सभी गाड़ियों में 20 से 25 प्रतिशत सीटें तत्काल श्रेणी में डाल दी गई हैं। पहले यह अनुपात 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं था। परेशान यात्री 150 रूपए तत्काल शुल्क चुका कर आरक्षण हासिल कर रहे हैं। बात इतनी सी भी नहीं है। किसी को पटना जाना है और कोलकाता जाने वाली गाड़ी में तत्काल टिकट लेता है तो उसे किराया कोलकाता तक का चुकाना पड़ता है। यह सब ऐसे नियम हैं जिनसे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। लेकिन लालू की नजर मुनाफे से हट ही नहीं रही है।

यह अच्छा मौका था। यात्रियों की असुविधाओं को दूर किया जा सकता था। यात्री से गंतव्य तक का ही किराया वसूलने का ऐलान किया जा सकता था। तत्काल कोटे का अनुपात घटाया जा सकता था।

तत्काल श्रेणी के टिकटों का आरक्षण शुल्क घटाया जा सकता था। स्टेशनों पर पेयजल सुविधाएं बढ़ाई जा सकती थीं। खान–पान सेवा को दुरूस्त बनाया जा सकता था। डिब्बों के भीतर और स्टेशन परिसर में सफाई की व्यवस्था चाक–चौबंद करने की दिशा में पहल की जा सकती थी। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। लालू जी ने एक बार फिर से निराश किया। ■

–लेखक पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री है।

यूपीए सरकार का फेयरवेल बजट : लालकृष्ण आडवाणी

16 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट के भाषण में श्री प्रणव मुखर्जी ने यह बात स्मरण करा कर बड़ा अच्छा किया कि 2004 में यूपीए सरकार को आम आदमी के साथ किए गए वायदों के आधार पर चुना गया था।

इस सरकार के 5 वर्ष के शासन काल के अंत में जो लोग उच्चतम आर्थिक स्थिति में आते हों वे खुश हो सकते हैं क्योंकि वे अरबपति या खरबपति बन गए हों, परंतु जहां तक आम आदमी की बात है वह तो बदहाली की हालत महसूस कर रहा है।

आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की बुरी तरह से बढ़ रही कीमतों के कारण मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरेलू बजट को बुरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। पिछले वर्ष से तेजी से बढ़ती जा रही बेरोजगारी की समस्या तो और भी कष्टदायक बन गई है जिसके पीछे प्रारंभिक कारण तो हमारी अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी रही है और फिर विश्व भर में छाई मंदी ने और कहर ढाया है।

अपने भाषण में श्री मुखर्जी ने कहा है कि 'भारत की सफल गाथा के नायक हमारे किसान रहे। उनकी कड़ी मेहनत से देश की 'खाद्य सुरक्षा' सुनिश्चित रही। कितनी बड़ी विडंबना है कि यह सरकार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों को शाबाशी देती है और फिर भी इन्हीं पांच वर्षों में हजारों–हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों ने तो खाद्य सुरक्षा प्रदान की और वही सरकार इन 'वास्तविक नायकों' की जीवन–रक्षा करने में बेहद विफल रही।

यह यूपीए सरकार के 5 वर्ष कार्यकाल का आखिरी बजट है। दरअसल यह 'फेयरवेल' अर्थात अलविदाई का बजट है और इस बजट में ऐसे पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि लोग कांग्रेस और इस सरकार को भी अलविदा कह देंगे।■

पृष्ठ 12 का शेष

जाएगा। यदि राज्यों के घाटों को और जोड़ दें तो यूपीए के शासनकाल में तो पूरा देश ही राजकोषीय संकट की एक अनुपम मिसाल बन कर रह जाएगा।

7. जहां तक –उच्च तथा अधिक कुशल राजकोषीय हस्तांतरण सुनिश्चित करने की बात है, इसे वित्तीय आयोग निर्धारित करता है। जहां तक अधिक कुशल हस्तांतरण का प्रश्न है, उसमें यूपीए सरकार ने कुछ भी तो नहीं किया है।

यूपीए सरकार ने आम आदमी के नाम पर पिछले पांच वर्षों में देश पर शासन करने का दावा किया है और फिर भी उसके शासन में आम आदमी ने ही एक मात्र उसकी अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध के कारण सर्वाधिक दुख भोगा है। आज तक कभी भी आम आदमी को जितना दुख आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उठाना पड़ा है, उतना पहले कभी देखने को नहीं मिला, जो आज भी उतनी तेजी से बढ़ते हुए दो अंकों तक पहुंच गया है, आम आदमी की आजीविका चली गई है, उसकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।

अंतरिम बजट वैसा ही सिद्ध हुआ है जैसा कि हम लगातार कहते भी आए हैं कि 28 फरवरी 2008 को प्रस्तुत किया गया बजट एक दम धोखे–कपट का बजट था। आज उस बजट के चिथड़े–चिथड़े हो गए हैं जिसे हम खर्च और राजस्व दोनों मामले में देख रहे हैं। अनेक मदों पर कम धन की व्यवस्था करने से और बहुत सी अन्य मदों पर कुछ भी धन की व्यवस्था न करने के कारण वित्तमंत्री ने एफआरबीएम लक्ष्यों के अंदर रहने का भले ही दावा किया हो, जो झूठा निकला। आज वह और उनकी सरकार का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है।

आज जब देश पूरी तरह से पहले ही गहरे आर्थिक संकट में डूब गया है तो सरकार का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह इसके उपचार के लिए कड़े और कारगर उपाय करती। वित्त मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि यूपीए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से त्याग दिया है। ■

देश की अर्थव्यस्था को सुधारने के लिए कड़े उपाय आवश्यक : लालकृष्ण आडवाणी

यूपीए सरकार ने जिस तरह की अर्थव्यवस्था की हालत दिखाई है, वह उससे भी कहीं दुर्दशा की हालत में है, बल्कि इससे भी बुरी होनी वाली है। भाजपा और राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 14 फरवरी को अपने निवास स्थल पर बुलाई गई अर्थशास्त्रियों की एक गोलमेज बैठक में यह आम सहमति बनकर सामने आई।

अनेक अर्थशास्त्री इस बात से निराश थे कि भारत में आज भी सरकारी उच्चाधिकारी अर्थव्यवस्था की बदहाली को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि समग्र रूप से राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा जीडीपी के 13 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो आज तक सबसे अधिक बड़ा घाटा है। उनकी यह भी राय थी कि विश्व की अर्थव्यवस्था में छाई मंदी से बहुत पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर में आ गई थी।

अनेक अर्थशास्त्री इस बात से निराश थे कि भारत में आज भी सरकारी उच्चाधिकारी अर्थव्यवस्था की बदहाली को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि समग्र रूप से राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा जीडीपी के 13 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो आज तक सबसे अधिक बड़ा घाटा है। उनकी यह भी राय थी कि विश्व की अर्थव्यवस्था में छाई मंदी से बहुत पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर में आ गई थी।

बैठक में भाग लेने वालों अन्यमहानुभावों के नाम इस प्रकार हैं–

1. श्री अरूण शौरी
2. श्री किरीट सोमैया
3. श्री पीयूष गोयल
4. श्री विजय कपूर
5. श्री अनिल बैजल
6. श्री जगदीश शेट्टीगर
7. श्री अजित डोवाल
8. श्री टी.एन. निनान
9. डा. सुबीर गोकरन
10. प्रो. विवेक डिब्रॉय
11. प्रो. डी.बी. गुप्ता
12. प्रो. एस. एल. राव
13. डा. अमित मित्रा
14. डा. बिमल जालान
15. श्री एस. नारायण
16. श्री विनायक चटर्जी
17. श्री प्रताप भानु मेहता
18. श्री बकुल ढोलकिया

बहुत से भागीदारों का मानना था कि जब 2007 के अंत में स्टाक मार्केट में 'सट्टेबाजी' का दौर चलने लगा तो सरकार ने कुछ नहीं किया। परिवर्तनशील अल्पकालिक पूंजीगत प्रवाह को उस समय नियमित नहीं किया गया जबकि वैसा किया जाना चाहिए था। बाद में, इस व्यवस्था से तरलता को बाहर निकालना और साथ ही ब्याज दरें बढ़ाने से न केवल मुद्रास्फीति बढ़ती चली गई बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से क्रेडिट व्यवस्था भी चरमरा गई।

परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में नौकरियों में छंटनी होने लगी। कितनी नौकरियां गई, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है, जो संभवतः 50 लाख से एक करोड़ की संख्या हो सकती है क्योंकि इनमें से 90 प्रतिशत ऐसी नौकरियां हैं जो अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में हैं।

इस बारे में श्री आडवाणी ने कहा कि यदि 2009 के संसदीय चुनावों में एनडीए सत्ता में आती है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उच्चतम प्राथमिकता इस बात को दी जाएगी कि 'रोजगार पैदा हों और अधिक रोजगार पैदा हों, बल्कि और भी अधिक रोजगार पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि भारत के विकास माडल में कांतिकारी परिवर्तन लाया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत के आर्थिक विकास की भावी रणनीति में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रों को सही स्थान प्राप्त हो ताकि हम 'हर हाथ को काम, हर

खेत को पानी' के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। श्री आडवाणी ने महसूस किया कि श्रम कानून नौकरियों को संरक्षण देने में पूरी तरह से प्रभावहीन रहे हैं और इसलिए इन पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

बैठक में भाग लेने वालों ने इस बात की चेतावनी दी कि जब तक हम राजकोषीय, मौद्रिक और सार्वजनिक निवेश पर एकजुट होकर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुशासन के जरिए सरकारी तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और योजनाओं को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों के मामले में न्यायिक सुधार किए जाएं ताकि ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं दूर की जाएं और भारत में कारोबार करने को सहज बनाया जा सके।

बहुत से भागीदारों ने इस पर खेद प्रगट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिल्ली–मुम्बई रेल भाड़ा कोरिडोर परियोजना आदि अनेक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को यूपीए के शासनकाल में रोक दिया गया। उनका परामर्श था कि अगली सरकार को इन सभी तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरीय तथा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की जरूरत होगी।

बहुत से भागीदारों ने भाजपा की लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने की मांग का समर्थन भी किया जिससे बिना किसी लीकेज के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कारगर ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके।

बहुत से अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा के नकारात्मक सुधारों के परिणामों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को देखते हुए दक्षता विकास पर जोरदार ढंग से पहल करने की मांग की। उन्होंने कृषि तथा एसएमई क्षेत्र में नई टेक्नॉलाजियों के प्रसारण के लिए बड़े राष्ट्रीय कोष का प्रस्ताव भी किया।

सभी भागीदारों का एकमत था कि देश का सबसे बड़ा संकट विश्वास का संकट है। नई सरकार का पहला काम तात्कालिक तथा दीर्घकालिक दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए साहसी एवं शीघ्र निर्णय लेकर लोगों में विश्वास बहाली करना है। हाल के महीनों में श्री आडवाणी ने सुशासन तथा विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के सिलसिले में यह गोलमेज बैठक आयोजित की थी। भाजपा के वरिष्ठ नेतागण श्री जसवंत सिंह, श्री यशवंत सिन्हा, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरूण जेटली ने भी इस बैठक में भाग लिया। ■

'वित्त मंत्रालय को अनाथ बना दिया यूपीए ने'

भाजपा ने यूपीए सरकार पर विश्वव्यापी मंदी के दौर में भी वित्त मंत्रालय को अनाथ छोड़ने का आरोप लगाया है। एनडीए सरकार में वित्त मंत्री रहे श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि किसी सरकार ने वित्त मंत्रालय के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, जैसा यूपीए कर रही है। यूपीए सरकार में ऐसे काबिल लोगों का अकाल है, जो वित्त मंत्रालय संभाल सकें।

श्री सिन्हा ने कहा कि आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक मंदी के गंभीर स्वरूप सामने आने वाले हैं और चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार में कोई वित्त मंत्री नहीं है। मनमोहन ने पूर्व वित्त मंत्री को गृह मंत्री बना दिया और खुद वित्त मंत्रालय का प्रभार ले लिया लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद से वित्त मंत्रालय भी विदेश मंत्री के हवाले है। उसका कोई पूर्णकालिक मंत्री नहीं है।

भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी की आर्थिक विशेषज्ञों के साथ हुए विचार–विमर्श के बारे में सिन्हा ने कहा कि मंदी के बुरे असर दिखने के बावजूद यूपीए सरकार इसे नकारने वाली मुद्रा में है। उसे वह कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो मंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। सरकार केवल गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल की पहली तिमाही कठिनाइयां लेकर आई है लेकिन इससे भी कठिन समय अभी आने वाला है। उत्पादन घट रहा है। मांग घट रही है। रोजगार पर खतरे पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना था कि मंदी का यह बीज 1997 में ही बोया गया था, जब अर्थव्यवस्था में बूम आया था लेकिन वह बुलबुला अब फट गया है। एक अनुमान के अनुसार मंदी के इस दौर में एक करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनमें से 90 प्रतिशत गैर संगठित क्षेत्र में होंगे। श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि आडवाणी जी ने विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान कहा कि यदि एनडीए सत्ता में आती है तो उसकी प्राथमिकता अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की होगी। कृषि और उद्योग एनडीए सरकार की प्राथमिकता होंगे। रोजगार गंवाने में श्रमिक कानून असरकारी नहीं रहे हैं। श्री आडवाणी का कहना था कि सरकार श्रमिकों के हितों के अनुसार श्रमिक कानून बनाएगी ओर राजस्व निगरानी पर जोर देगी। राष्ट्रीय पहचान पत्र दिए जाएंगे, ताकि कल्याणकारी योजनाएं प्रभावकारी ढंग से लागू की जा सकें। ■

सभी सुधि पाठकों को
कमल संदेश परिवार की ओर से
रंगों के त्यौहार होली
की हार्दिक शुभकामनाएं।

सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज माफ करेंगे : राजनाथ सिंह

jk ष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद करते हुए ऐलान किया है कि सत्ता में आने पर आडवाणी सरकार देश के 12.50 करोड़ किसान परिवारों के कर्ज माफ कर देगी और उन्हें चार प्रतिशत से भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। गठबंधन ने सरकार आने पर उद्योगपतियों को सब्सिडी देने की बजाय किसानों के खाते खोलकर उन्हें सीधी सब्सिडी देने और ट्रैक्टर आदि के ऋण पर उसकी कीमत से ज्यादा की जमीन बैंकों में बंधक न रखने की भी घोषणा की है।

इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं सांसद अजय सिंह चौटाला की 662 किलोमीटर लम्बी जनाक्रोश पदयात्रा के समापन समारोह के रूप में इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में आयोजित एक बड़ी रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से उक्त घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पार्टी के नागपुर सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और केन्द्र में गठबंधन की सरकार आने पर किसानों को बड़ी रियायतें दी जाएंगी।

बैंकों द्वारा ट्रैक्टर आदि के लिए किसानों की पूरी जमीन गिरवी रखे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि ऋण के बदले किसान की जमीन गिरवी न रखी जाए और सिर्फ ट्रैक्टर को ही गिरवी रखा जाए। भाजपा अध्यक्ष के इस विचार का रैली में मौजूद जनसमूह ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्य रूप से महंगाई को मुद्दा बनाया और कांग्रेस की केन्द्र और राज्य सरकारों पर पानी, सड़क, खाद और बिजली उपलब्ध न करवा पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि इन तमाम दिक्कतों को आडवाणी राज में दूर कर दिया जाएगा।

आतंकवाद के मुद्दे पर भी मनमोहन सिंह सरकार को निशाना बनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की ही देन है। उन्होंने कहा कि बुजदिल नेतृत्व आतंकियों का सफाया नहीं कर सकता और पूरी दुनिया को स्पष्ट तौर पर यह बता दिया जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की धरती से आतंक नहीं रूका तो भारत सीधी कार्रवाई कर देगा। इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला ने इस मौके पर रैली में उमड़े जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनाक्रोश पदयात्रा को मिली व्यापक सफलता से पूरे प्रदेश में हलचल है।

इस मौके पर हुड्डा सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि सेज के नाम पर किसानों की धरती छीनी गई है और अब तक 35 हजार एकड़ भूमि का सीएलयू दिया गया है जिसकी वजह से 60 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाखों लोगों को रोजगार देने के प्रलोभन देकर सत्ता में आई थी लेकिन अब तक 25 हजार लोगों को रोजगार से वंचित किया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह का आईएमटी रोहतक में दाह संस्कार किए जाने पर यह कहते हुए नाराजगी जाहिर की कि यह स्थान नए उद्योग लगाने के लिए प्रस्तावित है। आईएमटी चौधरी रणबीर सिंह के नाम पर संग्रहालय बनाने की हरियाणा सरकार की घोषणा पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगर संग्रहालय बनाना है तो वह दीनबंधु सर छोटू राम के नाम पर बनना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि गठबंधन हरियाणा की सभी दस सीटें जीतेगा।

जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने महंगाई, भ्रष्टाचार, सत्यम घोटाले और मुम्बई हमलों की चर्चा करते हुए रैली में उमड़े जनसमूह ने केन्द्र और राज्यों की कांग्रेस सरकारों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि देश पर शासन करने के लिए कांग्रेस ने हमेशा राज्यों और धर्मों को आपस में लड़वाया है। उन्होंने कहा कि आज देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के बाद केन्द्र में एनडीए की सरकार होगी और वह लोकसभा की सभी सीटें जीतेगी।

प्रदेशभर में जनाक्रोश यात्रा की अगुवाई करके चंडीगढ़ के सर्कस मैदान में पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव एवं सासंद अजय सिंह चौटाला ने लोगों से कांग्रेस शासन को उखाड़े का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि वह

एनडीए किसानों को चार प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करायेगा : राजनाथ सिंह

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का समग्र विकास तभी संभव है जब देश के ग्रामीण अंचल में रह रहे 12 करोड़ किसान परिवारों का विकास किया जाए तथा एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में न सिर्फ किसानों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण ही उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि सरकार या बीमा कम्पनी द्वारा कृषि आमदनी बीमा योजना के तहत किसान की फसल की आमदनी कम होने पर भरपाई भी की जाएगी। राजनाथ सिंह बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में इनेलो–भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई जिला स्तरीय विजय संकल्प रैली में उपस्थित जनसमूह को बतौर मुख्यातिथि सम्बोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज भी मुख्यरूप से मौजूद थी। इस मौके पर इनेलो के जिलाध्यक्ष मूलचंद शर्मा द्वारा भाजपा के शीर्ष नेताओं का हरी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने इनेलो नेताओं को केसरिया रंग की पगड़ी पहनाई। जबकि मंच का संचालन प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया।

रैली में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि 61 वर्षों की आजादी में 54 वर्ष तक देश में कांग्रेस की हुकूमत रही है, किन्तु बावजूद इसके आज देश की गिनती गरीब देश के रूप में हो रही है।

उन्होंने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ही हमेशा से सरकार हासिल करने के लिए राजनीति करती आई, जबकि भाजपा देश व समाज के लिए राजनीति करती है। उन्होंने घोषणा कि की केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में किसानों को चार प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ–साथ किसान की आमदनी कम होने पर उसकी भरपाई के लिए प्रत्येक किसान परिवार से एक युवक को नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं किसानों को सीधे तौर पर सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के बैंकों में खाते खुलवाए जाएंगे और जिस तरह से सब्सिडी उद्योगपतियों को दी जा रही है उसको सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने यूपीए सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि आज इस सरकार से समाज का हर वर्ग परेशान दिखाई दे रहा है।

किसान की हालत दयनीय है न तो किसान को बिजली व पानी ही मिल पा रहा है न ही खाद। इसके अलावा किसान को उसकी फसल का समर्थन न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को पूंजीवादियों की हितैषी करार दिया। उन्होंने रैली में उपस्थिजनों को कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। ■

जननायक चौधरी देवीलाल की संघर्ष की परम्परा का हिस्सा है और जुल्म के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और इनेलो का विश्वास का रिश्ता है वह हमेशा साथ–साथ है।

गठबंधन की इस रैली में भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष आत्मप्रकाश मनचंदा, पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आई.डी. स्वामी, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रतन लाल कटारिया, पार्टी नेता कैलाश शर्मा के अलावा पूर्व सांसद कैलाश सैनी, चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, चौधरी सम्पत सिंह, भाजपा की डॉ. कमला वर्मा और राज्यसभा सदस्य तरलोचन सिंह ने भी विचार व्यक्त किए।

इस मौके पर सर्वश्री अभय चौटाला, कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री शशिपाल महता, सुरेन्द्र दहिया, कैलाश शर्मा, सुशील इंदौरा, मोहम्मद इलियास, तेलूराम जोगी, शेर सिंह बडशामी और जसविन्द्र सिंह आदि नेतागण प्रमुख रूप से मौजूद थे।■

किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार : आडवाणी

Hkkजपा ने पूर्वांचल के गढ़ गोरखपुर से 15 फरवरी को चुनावी शंखनाद किया। इस मौके पर आयोजित 'राष्ट्र रक्षा विजय संकल्प' रैली में पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री लालकृष्ण आडवाणी ने देश की तरक्की के लिए यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा, 'गैर भाजपा शासित राज्यों में किसानों की हालत खराब है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी सरकार आने पर किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

श्री आडवाणी ने महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हाल ही में जो थोड़ी मंदी देखने को मिली है वह वैश्विक स्तर पर आई मंदी का असर है। मौजूदा यूपीए की सरकार ने आसमान छूती महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रभावी नहीं उठाया। श्री आडवाणी ने एक तरफ यूपीए सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ भाजपा शासित प्रदेशों की खुशहाली का हवाला दिया। श्री आडवाणी ने कहा भाजपा शासित राज्यों में जनता खुशहाल है, अल्पसंख्यक भी सुरक्षित हैं। गुजरात और वहां के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कांग्रेस दुष्प्रचार करती रही है। जबकि गुजरात के मुसलमानों में प्रति व्यक्ति आय देश के दूसरे राज्यों से ज्यादा है।

श्री आडवाणी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे 1951 से राजनीति में है और तब से लेकर 2004 तक के चुनाव में भाग लिया है। लेकिन इतना कमजोर शास कभी नहीं देखा। पिछले पांच साल का जो कष्टदायी शासन देश ने देखा है उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर फैसला दस जनपथ से होता है। श्री आडवाणी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए अफजल को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया।

गोरखपुर के भाजपा नेताओं के मुताबिक जिस महाराणा प्रताप कॉलेज में रैली की गई उसी कालेज से भाजपा ने इससे पहले जब रैली की थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी। इसी वजह से पार्टी ने फिर इस जगह को चुनावी शंखनाद के लिए चुना। गोरखपुर के गोलघर को भगवा झंडों से पाट दिया गया था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपीए की सरकार ने पिछले पांच साल में कमर तोड़ महंगाई, बेराजगारी, और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। जबकि राजग सरकार ने किसानों को सस्ते दर पर कर्जा दिलाया था। उनका कहना था कि भारत तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा। श्री राजनाथ सिह ने कहा कि केन्द्र में अगर लालकृष्ण आडवाणी की अगुआई में सरकार बनी तो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर, मशीन खरीदने पर बैंकों में सारी जमीन बंधक नहीं रखनी होगी। मशीन के मूल्य के बराबर की जमीन बंधक रखने पर उन्हें कर्जा दिया जाएगा। किसानों के सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। और आपदा, बाढ़ या सूखा आने पर उस दौरान के कर्जों ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

इसके पूर्व रैली के आयोजक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश बीमार चल रहा है। उन्होंने मुलायम और मायावती को राहु–केतु बताया और कहा ये दोनों उत्तर प्रदेश में जातिवादी संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश माओवादी गतिविधियों और माफिया संस्कृति का अड्डा बनता जा रहा है। देश और प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है। केन्द्र में भाजपा की सरकार होती तो नेपाल की अस्मिता खतरे में नहीं पड़ती। उन्होंने देश की मजबूती के लिए आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत बतायी और इसके लिए युवाओं से अपील की कि वे संकल्प लेकर अभी से तन, मन, धन से इस पुनीत कार्य में जुट जाएं। रैली को पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिमन्यानन्द, राष्ट्रीय महासचिव श्री अरूण जेटली, प्रदेश चुनाव प्रबंधन के प्रभारी कलराज मिश्र, भाजपा नेता श्री विनय कुमार सिंह बिन्नू, महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, विधायक श्री विजय बहादुर सहित तमाम लोगों ने सम्बोधित किया। रैली का संचालन श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने किया।■

आतंकवाद को हल्के से ले रही है कांग्रेस : राजनाथ सिंह

आज उ.प्र. का बुरा हाल है पीने का पानी हो या बिजली चारों तरफ इसकी किल्लत बनी हुई है। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक और भाजपा ने मुसलमानों को देश का नागरिक माना है।

विजय के संकल्प के साथ भाजपा ने 10 फरवरी को विशाल रैली का आयोजन किया। भाजपा ने जहां केन्द्र की यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं आतंकवाद से लड़ने में कांग्रेस की दोहरी भूमिका पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस को आतंकवाद–महंगाई पर कंट्रोल न करने के लिए भर्त्सना भी की तथा सपा–बसपा शासनकाल की लोगों को याद दिलाई। भाजपा ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ चुनाव में जुटने पर जोर देते हुए कहा कि केन्द्र में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। बस यही जोश वह बरकरार रखें।

रामपुर स्थित फिजिकल कॉलेज स्टेडियम मैदान में विजय संकल्प समागम दिवस समारोह में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में भाजपा अपने चुनावी अभियान का श्रीगणेश रामपुर की सरजमीं से कर रही है। यहां के कार्यकर्ताओं का जोश देखकर दूसरे जिलों में भी चुनावी तैयारियां और तेज होंगी।

उन्होंने आतंकवाद और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। बोले पोटा जैसे सख्त कानून को खत्म करके केन्द्र सरकार ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है। अफजल गुरू को फांसी के बजाए उसे बचाने की तैयारी हो रही है। भाजपा आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ती।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन दलों को भी निशाने पर लिया जो भाजपा को साम्प्रदायिक कहते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा भी भाजपा को सांप्रदायिक कहती है लेकिन भाजपा के साथ सरकार बनाने से परहेज नहीं करती। उन्होंने कहा कि हम लड़ते हैं तो पीठ में छुरा नही घोंपते। भाजपा इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने भी कांग्रेस, सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए बोले कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा को वोट दें, अगर विनाश चाहिए तो कांग्रेस को।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता वह सिर्फ आतंकवादी होता है। आज उ.प्र. का बुरा हाल है पीने का पानी हो या बिजली चारों तरफ इसकी किल्लत बनी हुई है रामपुर जैसे जिले की पुलिस लाइन में भी अंधेरा छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक और भाजपा ने मुसलमानों को देश का नागरिक माना है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। फोरलेन हाईवे के निर्माण से लेकर दूर संचार में आए क्रांतिकारी परिवर्तन की याद दिलाई एवं किसानों के लिए चलाई गई लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को याद दिलाई।

प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी और प्रदेश चुनाव प्रमुख कलराज मिश्र ने भी भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों को गिनाते हुए भाजपा को वोट देने की अपील की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं रामपुर से लोकसभा प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद रामपुर का विकास तय है।

श्री नकवी ने कहा कि रामपुर की जनता की सेवा करने का मौका मुझे केवल 13 महीने ही मिला था। दिल्ली से रामपुर तक हाइवे हो या फिर विलासपुर में भाखड़ा पुल दोनों बड़े काम हमारे प्रयासों से हो रहे हैं। रामपुर में कोच फैक्ट्री लगाने के लिए भी हमने कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया।

इस दौरान उत्तराखंड के ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री विशन सिंह चुभाल समेत क्षेत्रीय अध्यक्ष लज्जा रानी गर्ग, क्षेत्रीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह, संगठन मंत्री रामेश, विधायक काशीराम दिवाकर, पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, पूर्व विधायक ज्वालाप्रसाद गंगवार, जिलाध्यक्ष बलदेव औलख समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। संचालन श्री गुप्ता और सूर्य प्रकाश पाल ने किया। ■

बांग्लादेशी घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर खतरा

✍ fdj.k ekgs'ojh

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 103 करोड़ थी। इसमें 1.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भी सम्मिलित है। असम के पूर्व राज्यपाल ले. जनरल अजय सिंह ने कहा था कि 6000 बांग्लादेशी वैध रूप से प्रतिदिन सीमा पार कर भारत में आ रहे हैं। यह संख्या लगभग 22 लाख प्रतिवर्ष होती है। वर्तमान में अवैध घुसपैठियों की संख्या 3 करोड़ अनुमानित है।

असम पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की स्थिति बड़ी भयावह है। 2001 की जनगणना के अनुसार असम में हिन्दू जनसंख्या की वृद्धि दर 19 प्रतिशत एवं मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर 35 प्रतिशत थी। यह व्यापक स्तर पर अवैध घुसपैठ का ही एक गम्भीर दुष्परिणाम है। घुसपैठ यदि इसी स्तर पर बनी रही तो वर्ष 2025 तक असम में हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाएंगे।

बांग्लादेशी समुद्री मार्ग से उड़ीसा में भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से आ रहे हैं। उड़ीसा में केन्द्रवाड़ा एवं जगतसिंहपुर तो अब छोटे बांग्लादेश के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। भारत का पूर्वोत्तर भारत से सम्पर्क एक छोटे से गलियारे से ही है। यह सिलिगुड़ी नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत का पूर्वोत्तर भाग से स्थलीय सम्पर्क समाप्त हो सकता है।

आज देश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिक मतदाता बन कर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। यही कारण है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के खतरों के प्रति आंखें मूंद कर चुप है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक सत्ता प्रीतिकर है। किन्तु वे यह भूल रहे कि यदि देश नहीं बचेगा तो राज किस पर करेंगे।

अवैध बांग्लादेशियों के विरूद्ध अखिल भारतीय असम विद्यार्थी संघ, जो आसु के नाम से जाना जाता है, ने 1983 से 85 के मध्य एक बड़ा आंदोलन चलाया। वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ समझौता कर सभी अवैध घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का वादा किया था। इसी के परिणामस्वरूप अवैध आप्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1985 पारित किया गया। किन्तु इस अधिनियम की प्रक्रिया जटिल, अप्रभावी एवं अव्यावहारिक थी। इसके कारण इस अधिनियम में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान एवं उनके निष्क्रमण का कार्य हो ही नहीं पाया। 12 जुलाई 2005 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह अधिनियम एक तरह से अवैध बांग्लादेशियों की ढाल बन गया था।

किन्तु मुस्लिम मतों के लालच में संप्रग सरकार ने 'विदेशी अधिनियम' में संशोधन कर दिया। संशोधन के माध्यम से असंवैधानिक घोषित अवैध आप्रवासी अधिकरण अधिनियम के प्रावधानों को ही 'विदेशी अधिनियम' का भाग बना दिया गया। अवैध घुसपैठ के विरूद्ध भारतीय विधानों में प्रावधान अत्यंत ही दुर्बल एवं अप्रभावी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन एवं यूरोपीय देश अपने यहां अत्यंत कड़े आव्रजन कानून बना कर अवैध घुसपैठ कर पूरा अंकुश रखते हैं। आज भारत की आंतरिक सुरक्षा को सर्वाधिक गम्भीर खतरा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें सोचती है कि वे अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कुछ भी हनीं कर सकती है। यह विवशता का भाव हमारी समस्याओं को अधिक गम्भीर बना रहा है।

केन्द्र सरकार ने अवैध घुसपैठ समाप्त करने के लिए कोई भी सैन्य व्यूह–रचना तैयार नहीं की है। राजनयिक प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। हमारा सीमा चौकसी का पूरा प्रबंधन अत्यंत लचर एवं अप्रभावी है। 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों को विधिक प्रक्रिया से निष्क्रमित करना लगभग असंभव है। इस प्रकिया में तो 100 से अधिक वर्ष लग जाएंगे। केन्द्र सरकार को एक विशेष विधान रचना करके, अत्यंत ही संक्षेपण प्रक्रिया का प्रावधान कर अवैध बांग्लादेशियों के निष्क्रमण के गम्भीर प्रयास करना चाहिए।

कल्पना कीजिए की यदि कभी देश में आंतरिक कलह अथवा विद्रोह की स्थिति आ जाए तो उस पर किस प्रकार नियंत्रण होगा। देश में 3 करोड़ से अधिक विदेशी अवैध रूप से रह रहे हों तो स्थिति कितनी भयावह होगी। आज बांग्लादेश भारत में आतंककारी गतिविधियों के संचालन का एक बड़ा केन्द्र बन चुका है। प्रशासन के निचले स्तर तक व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कामचोरी और राजनैतिक नेतृत्व की मतों की लालची नीतियों के चलते केवल 3–4 हजार रूपये प्रति व्यक्ति के व्यय पर सैंकड़ों विदेशी बांग्लादेश से भारत आ सकते हैं।

अवैध बांग्लादेशी आज भारत में

6000 बांग्लादेशी वैध रूप से प्रतिदिन सीमा पार कर भारत में आ रहे हैं। यह संख्या लगभग 22 लाख प्रतिवर्ष होती है। वर्तमान में अवैध घुसपैठियों की संख्या 3 करोड़ अनुमानित है।

आतंकवादी समूहों के लिए बड़ी संख्या में गुप्तचरी कर रहे हैं। सलीम करी मुज्जफरनगर का रहने वाला एक जन्मांध व्यक्ति था। इसने 9 वर्षों तक कश्मीर के कुपवाड़ा में रहकर भारत के विरूद्ध सशस्त्र आतंकवादी कार्यवाहियां चलाई। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण वह पाकिस्तान भाग गया। किन्तु थोड़े समय के बाद ही वह गुवाहटी में 5 अन्य आतंकवादियों के साथ भारत विरोधी गतिविधियां चलाने लगा।

सौभाग्य से वे सभी पकड़े गए। उसके द्वारा सुरक्षा बलों को दी गई सूचनाएं आंखें खोलने वाली थी। उसने बताया कि कितने ही भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान ले जाकर भारत विरोधी प्रशिक्षण दिया गया। भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में किस प्रकार आतंकवाद एवं गुप्तचरी का तंत्र विकसित किया गया। जयपुर में वर्ष 2008 में हुए आतंकवादी घटनाओं में बांगलादेश के आतंकवादी समूहों की संलिप्तता तो सभी जानते ही हैं।

वर्ष 2001 में तबलीग़ ए जमात का एक बहूत बड़ा सम्मेलन ढ़ाका में आयोजित हुआ था। यह मक्का में हज के लिए होने वाले एकत्रीकरण के बाद का सबसे बड़ा मुस्लिम एकत्रीकरण कहा जा सकता है। इसमें 40 लाख से अधिक मुस्लिम आए थे। भारत से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम इस एकत्रीकरण में गए थे। यहां पर भारत के विरुद्ध अत्यंत ही उत्तेजना पूर्ण एवं घृणित वक्तव्य बड़ी संख्या में दिए गए थे। ये वक्तव्य बांगलादेश के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक, सैन्य एवं राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में दिए गए थे। किसी ने भी इन वक्तव्यों के विरुद्ध एक भी टिप्पणी तक नहीं की थी। यह दर्शाता है कि बांग्लादेश में किस प्रकार भारत को एक शत्रु राष्ट्र मानने की भावनाएं विद्यमान है। आज भारत की आतंरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए नकली भारतीय मुद्रा बड़ी संख्या में चलाई जा रही है। बांग्लादेश नकली भारतीय मुद्रा आपूर्ति करने का सबसे बड़ा केन्द्र है। पूर्वोत्तर भारत में हिंसक गतिविधियॉं चलाने वाले संगठनों एवं नक्सली संगठनों के तार भी बांग्लादेश से जुड़े है। भारत के विरुद्ध आतंकवाद का एक बड़ा केन्द्र बांग्लादेश बन चुका है। अवैध घुसपैठ रोकने के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहचान पत्र की एक पूर्वाभासी योजना प्रारम्भ की थी। यह पूरी भी हो गई । योजना पर एक बड़ी धन राशि भी व्यय हुई। चाहे किसी होटल में कमरा लेना हो, विमान–पत्तन से उड़ान भरनी हो, घर खरीदना हो, बैंक में खाता खोलना हो या कोई भी काम करना हो, आपको इस पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यवश 2004 में सत्ता में आई संप्रग सरकार ने इस परियोजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया।

15 जनवरी 2009 को ही एक लोकहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए है। साथ ही एक राष्ट्रीय परिचय पंजिका के संधारण की भी आवश्यकता बताई गई। संप्रग सरकार नें सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 2006 में शपथ पत्र पर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए आश्वस्त किया था। किन्तु इस पर किंचित भी प्रगति नहीं हुई। अब भी समय है हम बांग्लादेश से होने वाले अवैध आव्रजन की समस्या की गम्भीरता को समझें। यदि अवैध घुसपैठ निर्बाध जारी रही तो, यह देश के लिए एक और विभाजन का आधार तैयार करेगी। ■

(लेखिका भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है)

आज देश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिक मतदाता बन कर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। यही कारण है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के खतरों के प्रति आंखें मूंद कर चुप है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक सत्ता प्रीतिकर है। किन्तु वे यह भूल रहे कि यदि देश नहीं बचेगा तो राज किस पर करेंगे।

यह सिर्फ कांग्रेस के वंशवाद का युवा चेहरा है : भाजपा

भाजपा ने कांग्रेस के युवा चेहरों की राजनीति को वंशवाद की परंपरा करार देते हुए कहा कि वहां आम युवा के लिए कोई जगह ही नहीं है। पार्टी ने कांग्रेस के असली चेहरे पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो मुखौटा दिख रहा है, नेतृत्व उसके हाथ में नहीं है। उसने लोकसभा चुनाव में लोगों से योग्यता के आधार पर फैसला करने का आह्वान किया है, न कि परिवार के नाम को देख कर। कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को बतौर युवा नेता उभारने को भाजपा मतदाताओं को भरमाने की चाल भर मानती है। उसके नेताओं ने इसकी काट के लिए जनता के सामने साफ किया है कि कांग्रेस वंशवाद को इस नए पैकेज में पेश भर कर रही है। राहुल उसके नेतृत्व वाले परिवार के वारिस भर हैं। भाजपा महासचिव अरूण जेटली ने कांग्रेस के युवा–युवा के राग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां आम युवा का प्रवेश ही निषेध है। जो हैं वे किसी न किसी राजनेता के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेतरा ही भ्रामक है। जो दिखते हैं उसे वे खुद ही नहीं मानते हैं। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने देश की जनता को कांग्रेस की चाल के प्रति आगाह करते हुए कहा कि वह कांग्रेस के युवा आधारित नारे के झांसे में न आए। जहां तक युवाओं की बात है तो उसके युवा नेता आम जनता के बीच से है ही नहीं। पार्टी नेता इसमें चौदहवीं लोकसभा में सानिया गांधी के बेटे राहुल गांधी से लेकर जतिन प्रसाद, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा, नवीन जिंदल, संदीप दीक्षित व सचिन पायलट जैसे कई युवा नेताओं के नामों का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने किसी आम परिवार से आकर राजनीति नहीं संभाली। ■

राष्ट्रवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

वरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने विचारधारा को सबसे बड़ी विरासत बताते हुए पार्टी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों व पदाधिकारियों को इस कसौटी पर खरा उतरने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि केवल भाजपा के पास ही अपना दर्शन है और उसने 20–25 साल में जो ऊंचाई हासिल की है, वैसे उदाहरण दुनिया में कम ही मिलते हैं।

अपनी विचारधारा व मार्गदर्शक डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इंटरनेट के जरिए देश दुनिया के सामने लाकर डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इससे अधिष्ठान जहां

अपनी विचारधारा से लोगों को रूबरू कराने में सफल होगा, वहीं वह इस पर आने वाले सभी तरह के सवालों का जवाब देकर अपने व संघ के बारे में भ्रांतियों को दूर करेगा।

इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में भाजपा की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बाळ आपटे के साथ संघ के सह सरकार्यवाह श्री सुरेश भैयाजी जोशी व वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगा हरि उपस्थित थे। वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर नेताओं से पांच सवाल भी पूछे गए। श्री आडवाणी ने पूछे गए सवाल के जबाव में कहा कि वे आईटी को गांव–गांव तक पहुंचाना चाहते है। भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने विचारधारा से भटकी पार्टी के सवाल को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा पर कल भी कायम थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भैयाजी जोशी ने सन 2020 में संघ के काम के कई गुना आगे बढ़ने का विश्वास व्यक्त किया।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने भाजपा व कांग्रेस के भ्रष्टाचार की तुलना के सवाल पर कहा कि राजग के छह साल के शासन में कोई दाग नहीं लगा, जबकि कांग्रेस के शासन में हमेशा घोटालों की गूंज होती रही। इस मौके पर निम्नलिखित छह राष्ट्रवादी पत्रकारों–

1. श्री मा. गो. वैद्य
2. श्री रामशंकर अग्निहोत्री
3. श्री आनन्द मिश्र अभय
4. श्री गोपाल सच्चर
5. श्री रमेश पतंगे
6. श्री सुधीर पाठक

को 'बौद्धिक योद्धा सम्मान' से नवाजा गया। इन राष्ट्रवादी पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर तथा प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया। ■

छुआछूत को राजनीति में स्थान नहीं : आडवाणी

वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सामाजिक जीवन की तरह ही राजनीति में भी अस्पृश्यता की कोई जगह नहीं है। जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में श्री आडवाणी ने कहा जब हम सामाजिक जीवन में छुआछूत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम राजनीति में छुआछूत के बारे में कैसे सोच सकते हैं।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और राजनीति जीवन में उन्हें आदर्श मानना चाहिए जिन्होंने राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कम्युनिस्टों से हाथ मिलाने की आलोचना की थी। आडवाणी ने कहा– हमने कभी अस्पृश्यता को नहीं अपनाया लेकिन कम्युनिस्टों ने हमेशा एक दूरी बनाए रखी और तिरस्कार का व्यवहार रखा।

इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक मंदी के समय में राष्ट्र के समक्ष शासन के लिए उपाध्याय का दर्शन ही एकमात्र विकल्प है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा– पूंजीवादी और मार्क्सवादी दोनों ही माडल न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से ढह चुके हैं और इन परिस्थितियों में एकात्म दर्शन मॉडल सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि दीनदयालजी के दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार मानने और जीवनशैली के लिए स्वदेशी की अवधारणा को अपनाने की बात है। ■

''सब किसान- एक समान'' के तहत सभी किसानों के कर्जे माफ हों

गत 7 एवं 8 फरवरी को नागपुर में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे ने ''कृषि प्रस्ताव रखा'', जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव में देश की खस्ता हालत के लिए कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए मांग की गयी कि सभी किसानों के कर्जे माफ किए जाएं और कृषि ऋण चार प्रतिशत के ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाए। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठ :

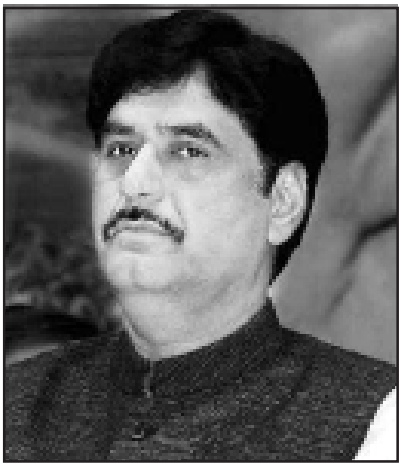

आज देश में कृषि की खस्ता हालत के लिए काँग्रेसनीत यूपीए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेवार है। सरकार के पास न तो कोई कृषि नीति है, न कोई दीर्घकालिक रणनीति, और न ही सुधार के लिए कोई ठोस कदम। आजादी के बाद पचास साल से ज्यादा देशपर राज करनेवाली काँग्रेस सरकार ने कृषि को प्राथमिकता नहीं दी। परिणामस्वरूप भारत में अभूतपूर्व कृषि संकट पैदा हुआ। कृषि क्षेत्र में न सार्वजनिक या निजी लागत बढ़ी न किसान की गरीबी दूर हुई। देश का पेट भरनेवाला किसान आज भारी संख्या में आत्महत्या कर रहा है। यह आसमानी नहीं सुल्तानी संकट साबित हुआ है।

पिछले साल सरकार ने किसानों को कर्जे के बोझ से बाहर निकालने का वादा करके कर्जमाफी योजना की घोषणा की। लेकिन इस योजना का लाभ 5 एकड से ज्यादा भूमि वाले करोड़ों किसानों को नहीं मिला। खासकर सिंचाई का लाभ न पाने वाले किसान तो सूखे ही रह गये। जिसने एक भी किश्त जमा की ऐसे लाखों प्रामाणिक किसानों को इस योजना से वंचित रखा गया। प्रामाणिक किसानों को दंडित करनेवाली यह कैसी योजना? यह योजना किसानों के साथ आज तक का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। 80 फीसदी किसानों को इसका कोई लाभ नही मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने माँग की थी कि – हर किसान का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ होना चाहिए। हम मानते है कि ''सब किसान एक समान, सबके साथ न्याय समान''। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि साहुकारों से लिए गए ऋण बैंक के ऋण में तब्दील कर किसान को लूट से छुटकारा दिलाना चाहिए। लेकिन काँग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

इस धोखाधड़ी का परिणाम सबके सामने है। आत्महत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है। जिस विदर्भ में यह अधिवेशन हो रहा है वहाँ इस योजना के लागू होने के बाद, यानी अप्रैल 2008 के बाद 1200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। और तो और, 2009 के मात्र 37 दिनों मे 92 किसान अपनी जान गँवा चुके हैं। काँग्रेस की गलत नीतियों का यह कच्चा चिठ्ठा है। आत्महत्यायें केवल विदर्भ में ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड समेत देश के अन्य भागों में भी लगातार जारी हैं। आलम ये है कि हर 8 घंटे में देश में कहीं न कहीं एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इस योजना की विफलता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।

एनडीए सरकार द्वारा गठित किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. स्वामीनाथन ने चेतावनी दी थी कि अगर जरूरी सुधार तुरंत नही किए गये तो देश में कृषि संकट और गहरा हो जायेगा। कृषि संकट कृषि तबाही में बदल जायेगा। काँग्रेस की नीति के चलते यह चेतावनी सही साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस नीत यूपीए सरकार की इस किसान विरोधी नीति की घोर भर्त्सना करती है।

भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ विश्वास है कि कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। जब तक गाँव, गरीब तथा किसान का भाग्य नहीं बदलेगा, तब तक देश सुखी और वैभवशाली नहीं बनेगा। इसलिए गाँव, गरीब, किसान ही हमारी आर्थिक संरचना की प्राथमिकता होनी चाहिए।

काँगेस सरकार ने कभी भी किसान के साथ न्याय नही किया। उसकी फसल को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। आज भी 60 फीसदी किसानों को निजी स्त्रोतों से जरूरी कर्जा लेना पडता है। उन्हें बैंकों से कर्जा नहीं मिलता। 85 फीसदी किसानों को बीमा योजना का संरक्षण नहीं मिलता है। कभी बाढ़ के रूप में, कभी सूखे के रूप में तो कभी फसल की बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को इस दुरावस्था से निकालकर न्याय देने का वादा करती है।

काँग्रेस सरकार की धोखाधड़ी का दूसरा सबूत भी सामने आया है। जिन थोड़े किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ

मिला, उन्हें नया कर्जा नहीं मिल रहा है। यह भी साबित हुआ है कि ऐसे 60 फीसदी किसानों को आज बैंक और अन्य वित्तीय संस्थायें दरवाजे में भी खड़ा होने नही देती हैं। उन्हें निजी स्त्रोतों का दरवाजा खटखटाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। काँग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त आघात पहुँचाया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था इसलिये शुरू की गई थी की कि किसान को कम से कम मूल्य मिलना सुनिश्चित हो। लेकिन काँग्रेस की विनाशकारी अर्थनीति ने इस धारणा को समाप्त कर दिया है। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रु. प्रति क्विंटल घोषित हुआ। लेकिन, खरीद के लिये न कॉटन फेडरेशन आगे आया, न नाफेड़। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि किसान 2400 रुपये में कपास बेचने पर मजबूर है। सरकार ने कपास और अन्य फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त निधि मुहैय्या नही करायी। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद करना कानूनन अपराध होना चाहिये।

काँग्रेसनीत यूपीए सरकार का सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। एनडीए के शासन में जहाँ खाद्यान्न के भंडार पूरे भरे पड़े थे वही काँग्रेस की गलत नीतियों के चलते वे भंडार खाली हो गये। काँग्रेस सरकार ने पहले तो किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया और फिर निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसान से खरीद की छूट दे दी। इस नीति के परिणामस्वरूप केवल 25–50 रुपये ज्यादा देकर निजी कंपनियों ने किसानों का अनाज हड़प कर लिया। सरकारी गोदामों में गरीब जनता को बाँटने के लिए, यहाँ तक कि राशन–व्यवस्था के लिए, पर्याप्त अनाज उपलब्ध नहीं हुआ। निजी कंपनियों ने भंडारण भी किया, कमॉडीटी एक्स्चेंज के जरिये दाम भी बढाये और देश की जनता को लूटा भी। महंगाई का यह भीषण दौर काँग्रेस की इस विफल नीति का घातक परिणाम है।

जो देश एनडीए के समय देश की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के बाद निर्यात करता था, वह यूपीए के कार्यकाल में खाद्यान्नों का आयात करने वाला देश बन गया। गेहूँ की पैदावार ठीक होने के बावजूद लाखों टन खराब गेहूँ विदेश से आयात किया गया। और तो और, काँग्रेस की नीति ऐसी रही कि जहाँ देश के किसानों को मात्र 800 रुपये कीमत मिली वहीं, विदेशी किसान को 1600 रुपये दाम मिला। काँग्रेस सरकार ने देश के साथ अजीब न्याय किया है।

भारतीय जनता पार्टी खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमें देश के किसान पर भरोसा है। अपनी मेहनत से वह देश को अनाज के मामले में स्वावलंबी बना सकता है। आवश्यकता है दूरदृष्टि की, आवश्यकता है किसानपरक नीतियों की, आवश्यकता है खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की। भारतीय जनता पार्टी मानती है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो नीतियों की जरूरत है– एक लंबे समय के लिए चलनेवाली उत्पादकता को बढ़ावा देकर उत्पादन बढ़ानेवाली समग्र कृषि नीति और दूसरी किसान को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करानेवाली मिली थी। भारतीय जनता पार्टी, इन दो नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती है।

दुर्भाग्य से काँग्रेस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली से भी छेड़खानी की। समर्थन मूल्य तय करने की प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने जानबूझकर कमजोर किया। भूमि का सही किराया, नैसर्गिक आपदा की नियमितता, कृषि में आयी अनिश्चितता तथा रिस्क जैसे घटकों का सही आकलन आज के समर्थन मूल्य प्रणाली में नहीं होता। इसमें सुधार करने के बजाय काँग्रेस सरकार ने समर्थन मूल्य–प्रणाली को और बिगाड़ दिया। इसे किसान पर अन्याय करने का एक साधन बनाया। कृषि मूल्य आयोग के धान समेत अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाने की सिफारिश को सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जहाँ सरकार ने आखिर गेहूं को 1080 रुपया भाव घोषित किया वहीं धान के साथ समान न्याय नहीं किया। आज इसी कारण देश को धान की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय जनता पार्टी मानती है कि समर्थन मूल्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये तथा उत्पादन खर्च पर 50 प्रतिशत रकम जोड़कर समर्थन मूल्य तय करने की कृषि आयोग की इस सिफारिश को मानना चाहिये।

खाद की कमी और कालाबाजारी यह काँग्रेस सरकार की देन है। कृषि–खाद–रेल मंत्रालय मे समन्वय के अभाव और उससे ज्यादा माँग का सही आकलन करने में सरकार की विफलता के कारण आज देश भर में खाद की भी किल्लत हो गयी है। वैकल्पिक खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि सरकारी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने खाद वितरण में भी बड़ी धांधली और पक्षपात किया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ पक्षपात किया गया है। राजनीतिक सोच के आधार पर किसान के साथ ऐसा अन्याय आज तक कभी नहीं हुआ। खाद के संदर्भ में स्पष्ट नीति की घोषणा समय पर न होने के कारण देश भर में किल्लत आयी, आंदोलन हुए और गोली भी चली। इस स्थिति की जिम्मेवारी सरकार की है।

कीटनाशकों के बारे में तो किसान अलग मुसीबत में है। सरकारी नियंत्रण न होने के कारण कीटनाशक ऊँचे दामों पर मिल रहे है। विदेशी कंपनियों की तूती बोल रही है। यही एक कृषि संबंधी वस्तु है जिसपर केंद्र सरकार ने 16 फीसदी एक्साइज लगाया है। कीटनाशकों की मार्केटिंग जोरों पर है लेकिन, उसकी गुणवत्ता परखने की कोई प्रक्रिया नहीं है। नकली कीटनाशकों की भरमार है, लाखों किसान इससे परेशान हैं। एनडीए के कार्यकाल में विकसित की गयी नियत्रंण प्रणाली को इस सरकार ने समाप्त किया।

बीज उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता को भी काँग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया। नये बीजों का निर्माण अनुसंधान पर निर्भर करता है। लेकिन यूपीए सरकार ने अनुसंधान के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कृषि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बाँटने वाले कॉलेज बनकर रह गये है। वहाँ अनुसंधान का काम समाप्त हो गया है। छोटे छोटे बीज–क्षेत्रों का विकास देश की जरूरत है। इस योजना को सरकार ने आगे नही बढ़ाया। आज अधिकांश सरकारी बीज उत्पादक संस्थान केवल आयात के एजेंट बन गये है। नयी–नयी फसलों में बीटी जीन्स का प्रयोग बढ़ रहा है। इसके परिणामों का सरकार ने कोई लेखा–जोखा नहीं किया है। बीज

के क्षेत्र में पहले आत्मनिर्भर रहा भारत आज परावलंबी हो गया है।

बीज–खाद–कीटनाशक के इस संकट के लिये काँग्रेस सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। और इसी संकट के चलते किसान की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। किसान को आज दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उसे लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ उसकी लागत लगातार आसमान छू रही है। कृषि का उसका गणित चरमरा गया है। लागत के खर्चों पर नियंत्रण प्रणाली बनाने में यह सरकार चूक गयी है।

भारतीय जनता पार्टी मानती है कि खेती में मुनाफा तभी होगा जब लागत के खर्चे ज्यादा न बढ़ें और किसान को लाभकारी मूल्य–प्राप्ति सुनिश्चित हो।

इस सरकार ने वादे तो बहुत किये लेकिन वह सबके सब खोखले साबित हुए। चाहे वह कृषि क्षेत्र के लिए 25 हजार करोड़ की विशेष राशि हो या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो– ढूंढने से भी इसका अस्तित्व कहीं नहीं मिलता। यह सब नारे के नारे ही रह गये। इन घोषणाओं का अमल कहीं दिखायी नहीं दिया। केंद्र कि सरकार ने पशुधन के महत्त्व को नही समझा और पशुधन विकास की कोई नीति भी नहीं बनायी। आज पशुधन का नाश हो रहा है और देश का भारी नुकसान हो रहा है। मछुआरे मत्स्य खेती करते हैं लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। आलू के किसानों की इस साल दुर्दशा हुई, कोल्ड स्टोशुरेज का खर्चा भी नहीं निकला। किसानों ने वहीं आलू छोड़ दिये लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। मंदी से उभरने के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देना चाहिये था लेकिन यह भी सरकार ने नहीं किया।

काँग्रेस सरकारने कृषि के आयात–निर्यात नीति के साथ भी खिलवाड़ किया है। जब किसान को बाजार में दाम मिलने लगता है तो सरकार तुरंत सुविधाएं देकर उस वस्तु की आयात षुरू कर देती है। जब किसान को बाजार में दाम मिलने लगता है तो सरकार तुरंत निर्यात पर रोक लगाती है। किसान को कभी–कभार लाभ मिलने की स्थिति को भी सरकार समाप्त कर देती है। बासमती चावल, चीनी, सोयाबीन और कपास के बारे मे सरकार की अनिश्चित आयात–निर्यात नीति के कारण किसान को जोरदार आघात लगता है।

किसान का अधिकार पत्र

1- ^lc fdlku ,d leku* ds rgr lc fdlkuksa ds dtZ ekQA
2- Ñf"k&_.k pkj izfr'kr ds C;kt nj ijA
3- fdlkuksa dh lfClMh lh/ks fdlku dksA
4- Ñf"k ds fy, i;kZIr fctyhA
5- gj [ksr dks ikuh] gj gkFk dks dkeA
6- NksVs fdlku dks vk; dh xkjaVh nsusokyh Qly bUde xkjaVh bU';kjsal LdheA
7- fdlku dks o`)koLFkk esa isa'ku
8- lHkh Qlyksa dks U;wure leFkZu ewY;A
9- mRiknu dh ykxr ij 50 Qhlnh jde tksMdj U;wure leFkZu ewY;A
10-fdlku deh'ku dh flQkfj'kksa dks ykxw djuksA

इस सरकार ने अमरीका के साथ एक कृषि संबंधी अनुसंधान (नॉलेज इनिशिएटिव्ह इन अॅग्रीकल्चर) किया है। आज तक देश को संसद में या संसद के बाहर पता भी नहीं है कि यह समझौता है क्या ? कहीं देश की जैविक विविधता पर आँच लाने की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंडा पर चलने की यह कोशिश नही है? इस समझौते के सारे पक्ष जनता के सामने आने चाहिये।

इस सरकार का प्रमुख अपराध यह है कि इसने एनडीए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिये शुरू किये गये सारे अच्छे कदमों को ठंड़े बस्ते मे ड़ाल दिया है। चाहे वह नदी जोड़ो योजना हो या किसान को आय की गारन्टी देनेवाली बीमा योजना हो। सरकार ने बजट भाषणों में इन योजनाओं की प्रशंसा तो कि लेकिन उसपर अमल नहीं किया। किसान चैनल बंद कर दिया और कृषि अनुसंधान का बजट समाप्त कर दिया। सरकारी गोदाम खाली कर दिये गये और किसान को लाभकारी मूल्य से वंचित रखा। पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण का ऐतिहासिक फैसला एनडीए सरकार ने किया था जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता, लेकिन यूपीए सरकार ने इस फैसले को अमलीजामा पहनाने से इन्कार किया। एनडीए सरकार ने डब्ल्युटीओ के मंच पर किसानों के हितों की पैरवी सफलतापूर्वक की थी किन्तू आज पर्दे के पीछे सरकार क्या माँग रही है इसका देश को कुछ भी पता नहीं है।

कृषि का विकास सीधे तौर पर सार्वजनिक निवेश और खासकर सिंचाई से जुड़ा है। एनडीए सरकार ने बडे पैमाने पर इन दोनों कामों के लिए धन मुहय्या कराया था लेकिन यूपीए सरकार ने प्राथमिकता ही बदल दी।

हमने किसान के लिए सस्ता कर्जा सुनिश्चित किया था आज फिर से यह कर्जा महंगा हो गया है। एनडीए ने करोड़ों किसान क्रेडिट कार्ड बाँटे थे, आज कर्जे के अभाव में वह केवल कार्ड बनकर रह गये है। जहाँ एनडीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया था वहीं इस सरकार ने उसको तहस–नहस कर दिया।

आम चुनाव देश के सामने है। यूपीए की सरकार जानेवाली हैं, इस जानेवाली सरकार से हम कोई माँग नहीं कर रहे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान का अधिकार–पत्र घोषित करना चाहती है। ■